www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 14 | गोरखपुर, 28 सितम्बर 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

इस हिंसा ने अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर यह घटना वहाँ की जनता के असंतोष और बेचैनी को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर यह संकेत देती है कि लंबे समय से किए जा रहे वादे और आश्वासन क्यों अधूरे रह गए और क्यों स्थानीय लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं?

संवाद से समाधान तक: लेह-लद्दाख में हिंसा का सबक

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने व संविधान के अंतर्गत विशेष संरक्षण देने वाली छठी अनुसूची में शामिल करने के लिये चल रहे आंदोलन का हिंसक एवं विध्वंसक होना, विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प और आगजनी की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ-साथ चिन्ताजनक है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और उन्होंने लेह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी और उसके बाहर खड़े वाहनों को फूंक दिया। आमतौर पर बेहद शांत रहने वाले लद्दाख के लिए यह बहुत बड़ी घटना है। दरअसल, पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दो सप्ताह से अनशन पर थे, उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी अनशनरत थे, जिनकी तबीयत बिगड़ने से जन-आक्रोश एवं हिंसा भड़की। इस हिंसा ने अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर यह घटना वहाँ की जनता के असंतोष और बेचैनी को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर यह संकेत देती है कि लंबे समय से किए जा रहे वादे और आश्वासन क्यों अधूरे रह गए और क्यों स्थानीय लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं?

सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए के प्रावधान हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया था। तब सरकार ने वादा किया था कि हालात सामान्य होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। लोगों ने सोचा था कि अब उनकी पहचान, संस्कृति और स्थानीय अधिकार और अधिक सुरक्षित होंगे। लेकिन इसके विपरीत उनकी आशंकाएँ बढ़ीं। उन्हें लगा कि संघ शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली से संचालित प्रशासन स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को समझने और पूरा करने में असफल हो रहा है। इसी कारण 6 साल बाद लोगों का भरोसा और सब्र डगमगाने लगा। इसी के चलते सोनम वांगचुक को अहिंसक आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, जो कतिपय कारणों से हिंसक हो गया। हालांकि, हिंसा के बाद वांगचुक ने अपना अनशन त्याग कर आंदोलनकारियों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की हिंसा से शांतिपूर्ण आंदोलन का मेरा संदेश आज विफल हो गया। अगर युवा गलत रास्ते पर जाएंगे, तो इससे हमारे वास्तविक उद्देश्य गुम हो जायेंगे। वाकई, लद्दाख के संयमी समाज को सतर्कता और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। वांगचुक का पूरा आंदोलन अहिंसक रहा है। सरकार से मतभेद होने पर भी उन्होंने बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा। उनके समर्थन में खड़े युवाओं को इसे समझना चाहिए। हिंसा से समस्या जटिल हो जाएगी। लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, उसे देखते हुए वहां के लोगों को कानून-व्यवस्था के प्रति विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। लद्दाख का केंद्रशासित प्रदेश बनना एक नये सूरज का उदय होना है और इसका वहां के लोगों ने स्वागत भी किया था। इस क्षेत्र को कश्मीर घाटी के वर्चस्व से मुक्ति मिली थी, पर वहां के लोगों की महत्वाकांक्षा को राजनीति रंग देकर एवं संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के अंधेरों में धकेल कर इसके वास्तविक उद्देश्यों को धुंधलाने की कुचेष्टा की गई है। हिंसा व आगजनी के बाद केंद्र शासित प्रदेश में संचारबंदी लागू की गई है। मीडिया माध्यमों से कुछ आंदोलनकारियों के मारे जाने की बात भी कही जा रही है। प्रतिक्रिया स्वरूप लेह बंद का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। यह प्रदर्शन कालांतर हिंसक प्रतिरोध में बदल गया। घटनाक्रम के बाद जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों ने हिंसा के लिये केंद्र को निशाने पर लिया है। कहा गया कि आंदोलनकारी लेह की अस्मिता को संरक्षण देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र व लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच आगामी 6 अक्टूबर, 2025 को एक वार्ता का दौर निर्धारित था, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्य शामिल होने वाले हैं। जब बातचीत होने ही वाली है, तो ऐसे विरोध प्रदर्शन की क्या

जरूरत थी? लेह के लोग अधूरे वायदों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनमें यह डर है कि अगर शासन उनके हाथ में न रहा तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होगा। इसी वजह से आंदोलनकारियों की हिंसक अभिव्यक्ति सामने आई है। वास्तव में, यह पूरा आंदोलन राजनीतिक प्रवृत्ति का है। इस प्रदर्शन को साफ तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि ताजा विरोध-प्रदर्शन केन्द्र से बातचीत को अनुकूल दिशा में ले जाने की रणनीति का हिस्सा है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें पूर्ण राज्य का अधिकार मिले ताकि वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें। साथ ही उनकी यह भी माँग है कि उन्हें संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए जिससे उनकी भूमि, संसाधन, परंपराएँ और रोजगार सुरक्षित रहें। रोजगार के अवसरों की कमी और सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं की उपेक्षा ने इस असंतोष को और गहरा किया है। लेह और कारगिल के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। लगातार समितियाँ बनीं, बातचीत हुई, आश्वासन दिए गए, लेकिन जब ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों के भीतर अविश्वास बढ़ा। निस्संदेह, लेह चीन की सीमा से लगा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, जिसके मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना जरूरी है। एक बड़ा मुद्दा क्षेत्र के युवाओं की बेरोजगारी रही है। युवाओं की दलील है कि क्षेत्र के युवाओं को पहले जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस सेलेक्शन कमीशन में राजपत्रित अधिकारी पदों के लिये आवेदन का मौका मिलता था, जो लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बंद हो गया। स्थानीय युवा अब केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की स्पर्द्धा में टिक पाने में दिक्कत महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय नौकरियों में युवाओं के लिये कोई विशेष अभियान भी नहीं चला। जिससे बेरोजगारों में खासा रोष व्याप्त रहा है।

आंदोलनकारी इसके अलावा कारगिल व लेह को लोकसभा सीट बनाने और स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की भी मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची में ऐसी स्वायत्त व अधिकार संपन्न प्रशासनिक इकाइयों का प्रावधान है, जिनके पास जल-जंगल व उद्योगों को लेकर क्षेत्र की संस्कृति व संरक्षण हेतु निर्णय करने का अधिकार होता है। लोग यह महसूस करने लगे कि उनकी जान-माल की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। लद्दाख की जनता के भीतर असुरक्षा की भावना इसलिए भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमि और संसाधनों पर बाहरी दखल बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएँ जैसे हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स कमजोर कर दी गई हैं और महत्वपूर्ण फैसले केंद्र के हाथ में केंद्रित हो गए हैं। इससे यह भावना गहराती है कि स्थानीय समाज की आवाज को दबाया जा रहा है। जब लंबे समय तक विश्वास और संवाद की कमी बनी रहती है तो जनता के धैर्य का बाँध टूट जाता है। यह सिर्फ राज्य का दर्जा पाने की माँग नहीं है बल्कि यह आत्म-नियंत्रण, पहचान और न्याय पाने की जद्दोजहद है।

लद्दाख की जनता यह चाहती है कि उनके अधिकारों को संवैधानिक गारंटी मिले, उनके संसाधनों की सुरक्षा हो और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। यदि सरकार ने पहले जो आश्वासन दिए थे, उन्हें समयबद्ध और स्पष्ट तरीके से लागू कर दिया जाता तो शायद स्थिति यहाँ तक न पहुँचती। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार संवाद और विश्वास बहाली की दिशा में ठोस कदम उठाए। संवैधानिक गारंटी देकर, स्थानीय प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाकर, रोजगार और शिक्षा की योजनाओं को मजबूती देकर ही इस असंतोष को शांत किया जा सकता है। लद्दाख की जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके हित सुरक्षित हैं, तभी हिंसा और आक्रोश का माहौल शांति और भरोसे में बदला जा सकेगा। लोगों में यह विश्वास पैदा करना जरूरी है कि फैसलों में लद्दाख के हितों का ख्याल रखा जाएगा। इसका सबसे बेहतर तरीका है पारदर्शिता। वहीं, जनता को भी समझना होगा कि सरकार के लिए हर मांग मानना और तुरंत मानना संभव नहीं होता।

रायपुर में इस्पात संयंत्र में हादसा, छह लोगों की मौत

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गत दिनों शुक्रवार को एक निजी इस्पात संयंत्र में हुए हादसे में चार अधिकारियों और दो कर्मचारियों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में एक महाप्रबंधक समेत छह लोग घायल हुए हैं। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) लाल उमेद सिंह ने ह्यपीटीआई-भाषाह्न को बताया कि यह घटना राजधानी के बाहरी इलाके सिलतरा क्षेत्र में स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के संयंत्र में हुई। सिंह ने बताया कि शाम करीब 4.30 बजे घटना की सूचना मिलने के बाद, पुलिस दल को मौके पर भेजा गया और बचाव अभियान शुरू किया गया।

रायपुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया, संयंत्र में भट्ठी पिछले कुछ दिनों से बंद थी। शुक्रवार को उच्च दबाव वाले पानी का उपयोग करके भट्टी की दीवार और छत पर जमा स्लैग (अपशिष्ट उत्पाद) की मोटी परत को हटाने के लिए सफाई का काम चल रहा था। अचानक स्लैग का मोटा जमाव ढह गया, जिससे नीचे मौजूद लोग फंस गए।

उन्होंने बताया कि बचाव अभियान के दौरान मलबे से छह श्रमिकों के शव निकाले गए। वहीं छह घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संयंत्र प्रबंधन के एक अधिकारी ने बताया कि घटना दोपहर लगभग तीन बजे हुई और घायलों को तत्काल संयंत्र के भीतर स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान प्रबंधक जीएल प्रसन्न कुमार और कालीगोटला प्रसन्न कुमार, सहायक प्रबंधक घनश्याम घोरमारे और निराकार मलिक तथा दो सहायक तुलसी राम भट्ट और नारायण साहू के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में महाप्रबंधक ए चक्रधर राव, वरिष्ठ तकनीशियन दीपेंद्र महतो, कनिष्ठ तकनीशियन चंद्र प्रकाश पटेल और तीन अन्य श्रमिक घायल हुए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है तथा अधिकारियों को घायलों के लिए बेहतर चिकित्सा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तथा ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

मिग-21: टाइगर ऑफ स्काई की गौरवपूर्ण विदाई तकनीक से तरक्की की तरफ तेजी बढ़ रहा है बिहार: कृष्ण कुमार मंटू

चण्डीगढ़ के एयरबेस से मिग-21 की आखरी उड़ान के साथ मिग की विदाई केवल एक सुपरसोनिक फाइटर की विदाई नहीं है अपितु भारतीय वायु सेना के फाइटर बेडे से मिग की गौरवशाली अतीत की विदाई है। अपनी गति, शक्ति और मारक क्षमता के कारण नाम से ही दुश्मनों में दहसत बनाने वाले मिग-21 अपनी यात्रा के 62 वर्ष पूरे कर विदा हो रहा है। 1962 के युद्ध के कटु अनुभवों के बाद भारत ने अन्य विकल्प होते हुए भी सोवियत रुस के मिग-21 को प्राथमिकता दी। 1963 में चण्डीगढ़ में ही मिग ने भारतीय वायु सेना में प्रवेश किया और 26 सितंबर, 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सेनाप्रमुखों के बीच औपचारिक विदाई ली है। स्क्वाड्रनलीडर प्रिया सिंह ने अंतिम उड़ान भर कर मिग-21 को शानदार-यादगार विदाई दी। मिग-21 का 1965, 1971, करगिल, बालाकोट और ऑपरेशन सिन्दूर तक गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि मिग-21 के उड़ान के दौरान हुई दुर्घटनाओं ने इसे उड़ता ताबूत ही नहीं विडो मेकर तक कहा जाने लगा। दरअसल पाकिस्तान से युद्ध के दौरान अमेरिका के एफ-16 युद्धक विमान को गिरा कर सारी दुनिया को इसने आश्चर्य में ड़ाल दिया था। 1971 में ढ़ाका में गर्वनर हाउस पर बमबारी कर अपनी मारका क्षमता का लोहा मनवा चुका है। भारतीय वायु सेना में 800 से अधिक मिग का बेड़ा रहा है। इनमें से करीब 400 मिग के दुर्घटनाग्रस्त होने और करीब 200 पायलट और 50 नागरिकों की मौत के कारण गति, शक्ति और रफ्तार के बावजूद मिग-21 को उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। यह दूसरी बात है कि कुछ दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण हुई तो कुछ अन्य कारणों से।

मिग-21 सुपर सोनिक फाइटर विमान का निर्माण सोवियत रुस द्वारा 1950 के दशक के दौरान आरंभ किया और मिग की पहली उड़ान 1955 में हुई। 1962 के युद्ध के अनुभवों के कारण भारत को अपनी वायुसेना को मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की आपूर्ति के कारण भारत को भी अपनी वायुसेना को वेल इक्विप्ड करने की आवश्यकता महसूस हुई

और अमेरिका सहित अन्य देषों के फाइटर विमानों के विकल्प होने के बावजूद भारत ने सोवियत रुस के मिग फाइटर विमान खरीदने को पाथमिकता दी। हालांकि 1965 के युद्ध में मिग का सीमित योगदान रहा पर 1971 के युद्ध की तो भाषा ही मिग फाइटर ने बदल कर रख दी। अमेरिका के एफ-16 विमानों को मारगिराकर मिग विमानों ने ना केवल अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया अपितु दुनिया के देशों को दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर दिया। हालिया ऑपरेशन सिन्दुर में भी मिग विमानों ने महत्वूपर्ण भूमिका निभाई है।

मिग-21 अपनी उड़ान क्षमता, तेजी से आकाश में उंचाई पर जाने, ध्वनी से भी तेज गति से उड़ाने भरने और निशाने पर निशाना साधनें में सफल रहा है। दुश्मन देश तो मिग के नाम से दहशत खाने लगे थे। मिग-21 छोटे रनवे, कठिन हालातों में भी उड़ान भरने में सक्षम रहा है। अचानक हमले के हालातों में भी यह भरोसेमंद रहा है। सूई की नोक जैसे इस विमान में तापमान की समस्या के बावजूद इस विमान की उड़ान भरने में वायुसेना फाइटर गौरव महसूस करते रहे हैं। 2021 के बालाकोट के दौरान भी इसने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के 60 से अधिक देशों में मिग ने अपने पराक्रम को दिखाया पर मिग के निमार्ता सोवियत रुस से ही मिग की विदाई सबसे पहले आरंभ हुई। रशिया ने 1990 से ही मिग की विदाई आरंभ कर दी। चीन, पौलेण्ड, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकस्लोवाकिया, क्रोएशिया, हंगरी आदि इसे विदाई दे चुके हैं। हालांकि सीरिया, उत्तर कोरिया औद अफ्रिकी देशों में मिग सेना के हिस्से बने हुए हैं। भारत में मिग का लंबे समय का कार्यकाल रहा है।

फ्लाइंग काफिन जैसे नाम से बदनामी के बावजूद अपग्रेडेड मिग का भारतीय सेना में उपयोग होता रहा। निशाने पर लक्ष्य को साधने में सक्षम होने के बावजूद जिस तरह से इसके क्रेस होने की गति रही है उससे यह बदनामी का भी प्रमुख कारण रहा है। और यही कारण है कि मिग-21 की गौरवपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद अंततोगत्वा 62 साल की लंबी यात्रा के बाद इसे सम्मानपूर्वक विदाई दी गई है। देखा जाएं तो मिग ने भारतीय सेना में अपनी गौरवपूर्ण सेवाएं दी और भारतीय सैनिकों ने युद्ध के दौरान इसका जिस तरह से उपयोग किया वह भारतीय सेना के गौरव को बढ़ाने वाला रहा। यही कारण है कि मिग को गौरवपूर्ण समारोह में विदाई दी गई। जहां से इसकी शुरूआत हुई वहीं से इसको विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदाई समारोह में कहा कि भारतीय वायु सेना के इतिहास में मिग की सेवाओं को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मिग को भारत और रुस के बीच संबंधों से भी जोड़ के देखा जाता रहा है। खासबात यह कि उड़ता ताबूत कहलाने के बावजूद भारतीय वायु सेना में मिग ने 60 वर्ष से भी अधिक समय तक अपने सामर्थ्य से देश के जरुरत के समय अपेक्षाओं पर खरा उतरा। युद्ध या यौद्धिक गतिविधियों के दौरान मिग गैम चैंजर सिद्ध हुआ है। यही कारण है कि मिग को रिटायरमेंट की गौरवपूर्ण विदाई दी गई। अब भारतीय वायु सेना में स्वदेशी फाइटर तेजस मिग का स्थान लेगा। सुखाई, राफेल और तेजस आदि की उपस्थिति से आज भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे सक्षम और ताकतवर सेनाओं में से एक है। भले ही भारतीय वायु सेना के बेडे से मिग की विदाई हो गई है पर 1971 का युद्ध, करगिल, बालकोट, ऑपरेशन सिन्दुर और इसी तरह के अभियानों की चर्चा होगी तो मिग की गौरवपूर्ण सेवाओं को सम्मान के साथ याद किया जाएगा।

नई दिल्ली। सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित करके ही बिहार को पूर्वी भारत का आईटी हब बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार आईटी नीति-2024 में वे सभी प्रावधान किये गए हैं, जिससे कि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और बिहार को एक आईटी हब के रूप में विकसित किया जाए। सूचना एवं प्रावैधीकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू शनिवार को पाटलिपुत्र कॉलोनी में नवनिर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) इकाई का दौरा करके आईटी कम्पनियों को यहां मिल रही सुविधाओं का जायजा ले रहे थे। इस मौके पर आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र के कुल आधा दर्जन स्टार्टअप्स ने अपने कार्यों और नवाचार आदि की प्रस्तुति भी की।

यह एसटीपीआई भवन कुल एक लाख वर्गफीट में फैला है और इसमें कुल 103 प्लग एंड प्ले की व्यवस्था है। भवन का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए आईटी मंत्री ने कहा कि बिहार तकनीक से तरक्की की तरफ तेजी बढ़ रहा है। बिहार सरकार की आईटी नीति-2024 के तहत पहले से ही निवेशकों को पूंजीगत निवेश और रोजगार सृजन को लेकर कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत बिहार सरकार निवेशकों को पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, नेट स्टेट जीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे कई लाभ उपलब्ध करा रही है। पूंजी निवेश सब्सिडी के तहत कुल पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक) या ब्याज अनुदान सब्सिडी के तहत दस वार्षिक ब्याज अनुदान (परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक) पांच वर्षों के लिए दिया जा रहा है। जबकि 50 प्रतिशत सब्सिडी लीज रेंटल राशि पर पांच वर्षों के लिए देय है।

मंत्री कृष्ण मंटू ने कहा कि विद्युत बिल का 25 प्रतिशत वार्षिक प्रतिपूर्ति पांच वर्षों के लिए दिया जा रहा है। साथ ही रोजगार सृजन सब्सिडी के तहत ईएसआई और कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता योगदान की 100 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति जो अधिकतम पांच हजार रुपए प्रतिमाह प्रति कर्मचारी है, पांच वर्षों के लिए दी जा रही है। इस मौके पर सूचना प्रावैधिकी वभाग के विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, बेल्ट्रान के महानिदेशक (परियोजना) श्याम बिहारी सिंह, एसटीपीआई, पटना के अपर निदेशक राजीव कुमार और सी-डैक के निदेशक अभिनव दीक्षित मौजूद थे।

▶ नशे का हब बनता नेपालगंज

घर के साजो सामान, गहनें को बेचकर स्मैक पीता युवावर्ग

रुपईडीहा (बहराइच)। एक के बाद एक थाना क्षेत्रांतर्गत मेडिकल स्टोर्स महज नशे की सामग्री को बेचे जाने के लिए खोले जा रहे हैं। नशे की लत के शिकार हो का युवा घरों में चोरी छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे अपराधों का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। साइकिल मोबाइल बाइक चोरी तो आम बात हो चुकी है। नशे के भुक्तभोगी बताते हैं कि- थाने के सिपाहियों की अहम भूमिका को आमजन स्वीकार करते हैं।

जानकार सूत्रों की मानें तो कहने को तो वह आदर्श नगर पंचायत है ।पर नेपाल से सटी इस नगर पंचायत की हर गली में व गांवों में नशीली दवाएं व स्मैक की बिक्री बेतहाशा बढ़ती जा रही है जिसकी चपेट में गांव का युवावर्ग आसानी से इसकी चपेट में आता जा रहा है। घर के साजो सामान, गहनें को बेचकर युवावर्ग स्मैक पी रहा है। स्मैक के नशे के कारण न जाने कितने युवक व युवतियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कहा जाता है कि रुपईडीहा के थोक स्मैक विक्रेताओं ने युवाओं को फ्री की स्मैक देकर नशे का आदी बनाया है। इसी नशे की अधिकता ने रुपईडीहा की मरजीना, अशरीन, पप्पू तेली, छोटे बचऊ, टिल्लू निसार, शेखू, टिल्लू, निसार, शेरू, शेरा, यादव इस्माइल मेराज, रशीद व अहमद पुत्र चांद को मौत की नींद में सुला दिया है। दो युवकों का शव रामजानकी नगर वार्ड में पाया गया। एक नेपाली युवक शव सिंघानिया मार्केट तथा एक का शव भट्ठा

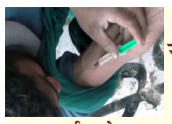

रुपईडीहा में फल-फूल रहे इन नशीली दवाओं के अनैतिक, कारोबार के जिम्मेदार ही नेपाली युवावर्ग को एक या दो ग्राम पुड़िया स्मैक दे देते हैं और वही थाने पर सिपाहियों को सूचना दे देते हैं तथा स्मैक खरीदार का हुलिया बताते हैं। ऐसे खरीदारों को पुलिस पकड़ कर अपने कार्यो की इतिश्री कर लेती है।

मोहल्ले में पाया गया। 2022 में भी इसी प्रकार की नशीली दवाओं की वैतरणी बह रही थी। स्थानीय पुलिस को दर किनार कर बीते 11व 12 जनवरी को एनसीबी लखनऊ और एसएसबी रुपईडीहा की संयुक्त टीम ने एक अभियान चला कर यहां 9 करोड़ की मूल्य की नशीली दवाओं को पकड़ा इस धंधे इस धंधे में लिप्त 6 कारोबारियों को दबोचा था। यह एक गुप्त अभियान था जिसकी कानो- आन खबर नही मिली थी। वर्ष भर बाद हाईकोर्ट से इनकी जमानत हुई अब प्रदेश सरकार इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है और क्षेत्र में नशे का धंधा चरम पर है। जबतक इसी तरह की सख्त कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक यह असामाजिक कारोबार बंद होने वाला नहीं है।

हालांकि रुपईडीहा की पुलिस चाक चौबंद होकर कार्य कार्य कर रही है। बावजूद इसके थाना क्षेत्र के शिवपुर मोहर निया, पंडित पुरवा, रंजीत बोझा, पचपकरी, नथुनिया चौराहा, राजा पेट्रोल पंप के आसपास का इलाका रामजानकी नगर, आदि क्षेत्रों में खुले आम स्मैक और नकली दवाएं बिक रही हैं। नशीली दवाएं बिक रही हैं। नशे का आलम यह है कि नशेड़ी घर के जेवर मेडिकल संचालकों को चुराकर देते है और और अपना नशा तलब करते हैं। ऐसी स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब ये युवा नशे के भयंकर आदी हो जाते हैं। नशीली दवाओं के कारोबारी मोबाइल और अन्य कीमती चीजों को रखते हैं और नशे की गोलियां दे देते हैं। बीते 23 दिसंबर की रात आठ बजे रुपईडीहा के चकिया रोड स्थित एक दुकानदार ने नेपालगंज की तीन युवतियों को नशीली दवाएं बेंची । पैसा न होने पर चांदी के कंगन और सोने की नथनी गिरवी रख लिए। प्रत्यक्षदर्शियों दर्शियों ने नवयुवतियों का पीछा किया लेकिन आगे चलकर वह अचानक गायब हो गई। रुपईडीहा से सटा नेपाली इलाका बांके का मुख्यालय नेपालगंज नशे का हब बन चुका है। अब रुपईडीहा सीमाएं तोड़ रहा है और यहीं सारी डीलें होती हैं ।

ड्रग इंस्पेक्टर के आने से पूर्व इन फर्जी मेडिकल स्टोर्स के शटर डाउन हो जाते हैं। जो यह सिद्ध करता है कि डी आई व उसे विभागीय कर्मियों की सूचना जानकारी पहले ही उपलब्ध हो जाती है। जांचकर्ता मात्र खाना पूर्ति के लिए ऐसे दुकानों की जांच करते हैं जहां नशीली दवाओं की कोई बिक्री नहीं होती है।

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस की पूर्व संध्या पर एक वैचारिक संगोष्ठी

आजमगढ़। ग्रामीण पुनर्निर्माण स्थापना एवं कॉमन हेल्थ के संयुक्त तत्वाधान में संस्थान द्वारा सामुदायिक स्वार था केन्द्र अतरौलिया के प्रांगण में आशा एवं आशा संगिनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस की पूर्व संध्या पर एक वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. आरती सिंह, अधीक्षक हरिश्चंद्र, एचओ जितेन्द्र कुमार, बीसी पोएम सुरेश पाण्डेय आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजदेव चतुर्वेदी ने कहाकि 28 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि बच्चा पैदा होने के 42 दिन के अंदर किसी महिला की मृत्यु होती है वो उस स्थिति में मातृ मृत्यु कहेंगे। हमारे जिले में 169 मौतें प्रतिवर्ष होती हैं। यह मातृ मृत्यु सुरक्षित या असुरक्षित या अन्य किसी भी से हो सकती है। इसे रोका जा सकता है। जिले में देने वाली ऐसी मौतों की शिकार महिलाएं इसलिए होती हैं जब कोई महिला बच्चा नहीं चाहती है और उसका गर्म रुक जाता है। अनचाहे गर्भ रुकने की वजह से उसकी मौत हो जाती है । सामुदायिक स्तर पर जागरूकता की कमी के कारण आज भी कई महिलाएं असुरक्षित तरीकों का सहारा लेती है। जिससे कि संक्रमण अत्यधिक रक्त स्राव, मृत्यु तक के मामले सामने आते हैं। हमारे देश में जब एमटीपी अधिनियम

आया था तो उसमें कहा गया था कि - अगर महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से खतरा है, भ्रूण में गंभीर असमानता है तो ऐसी स्थिति में एमटीपी एक्ट लगता है।

एचईओ जितेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे देश में शिक्षा की कमी है इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है और अनचाहा गर्भधारण होता है। जब महिला की नसबंदी होती है तो उसे दौरान आप सभी से अनुमति ली जाती है और उस नसबंदी में छावा डाला जाता है। अगर महिला आगे गर्भधारण करना चाहती है तो उसे छावे को निकाल दिया जाता है और महिला कुछ दिन के बाद गर्भधारण कर सकती है।

तिन्नी चावल के भाव में उछाल

गोरखपुर। मखाना ने जहां लोगों को राहत प्रदान करता है वहीं तिन्नी चावल में 10 वर्षों में सर्वाधिक तेजी देखने को मिल रही है। मखाना में 300 से 400 रुपए प्रति किग्रा. तक की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन तिन्नी चावल 10 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। वर्तमान में इसका भाव थोक में 240 रुपए और फुटकर में 270 से 300 रुपए प्रति किग्रा तक पहुंच गया है। पूर्वांचल में तिन्नी चावल के थोक कारोबारी (उमेश मद्धेशिया) के अनुसार- जनवरी में नई फसल आती है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मौसम की मार के कारण पैदावार मे 40 प्रतिशत की कमी आई है जिससे भाव से तेजी बनी हुई बनी हुई

पूर्वांचल की मंडियों में तिन्नी चावल रसड़ा दलेल नगर व जौनपुर से आता है। पिछले कई महीनों से नया माल नहीं आ रहा है, जिसके पास पुराना स्टाक है वही नवरात्र में बेचकर काम चलाएगा। उन्होंने बताया किलो चावल थोक में 160 से 20 रुपए प्रति किग्रा तक बिका था वह 40 से 50 रुपए की तेजी के साथ 250 पहुंच गया है।

एक अन्य मखाना कारोबारी (गोविंद अग्रवाल) के अनुसार, लंबे समय से मखाना भाव में तेजी बनी हुई थी। नई फसल आने के बाद भाव टूटे हैं और करीब प्रति किग्रा 300 से 400 रुपए नरमी आई है।

नवरात्रि के त्योहार में यह गिरावट ग्राहकों को राहतकारी है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 100 ग्रा. व 250 की पैकिंग में मखाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं जिससे व्यापारियों को तौलने का झंझट नहीं हो। इस मखाने का कारोबार दोगुना होने की संभावना है।

गोद लिए गांवों के विद्यार्थियों ने किय अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन

अयोध्या । आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 27वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर गोद लिए गए गांवों के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

यह प्रतियोगिताएं प्रदेश की राज्यपाल के निर्देश पर कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह के दिशा-निर्देशन में संपन्न हुईं। प्रतियोगिताओं में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने भाषण, चित्रकला, पेंटिंग, कहानी कथन, लोकगीत, निबंध और काव्य लेखन में हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं में ग्राम सिधौना, गोकुला, बिरौली झाम, जोरियम और डिली गिरधर के विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉ. डी.के सिंह, छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. डी. नियोगी, कुलपति के सचिव डॉ. जसवंत सिंह, निदेशक प्रसार डॉ. रामबटुक सिंह, डॉ. रमेश कुमार सिंह, डॉ. सीताराम मिश्रा, डॉ. सत्यव्रत सिंह, डॉ. रागिनी मिश्रा, डॉ. पीयूषा सिंह, डॉ. दिव्या सिंह, डॉ. श्वेता सचान और डॉ. प्राची शुक्ला सहित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

सामाजिक भेदभाव के बिंदुओं को मिटाने में सामाज का हित

सरकार द्वारा जारी दस सूत्रीय दिशानिदेर्शों में ध्यातव्य है कि- अब जाति के नाम, नारे या स्टिकर वाले वाहनों का केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत चालान किया जाएगा। यह तक कि - प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी जाति को दशार्ने से बचा जाएगा। अभी तक यही होता रहा है कि अपराधी जाति के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं और मजबूत हो जाते हैं। मजबूत होने के बाद वे अपनी जाति को पहुंचाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। साथ ही यह धारणा पनप रही है कि सभी लोगों को अपनी जाति की चिंता करनी चाहिए। यह भ्रांति भी फैल रही है कि- अपनी जाति के लोग या अधिकारी या नेता ही मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। ऐसी तमाम सामाजिक एवं प्रशासनिक खामियों से उबरने की आवश्यकता है। अन्याय के खिलाफ बिना जाति देखे खड़ा होना चाहिए। संविधान की भी मंशा यही है कि प्रत्येक नागरिक को अपने समाज की ताकत बनकर आगे बढ़ना चाहिए। स्मरणीय हो कि यह समाज मात्र एक जाति आधारित न रहे। जाति महत्वपूर्ण हैं और सबका विकास होना चाहिए, परन्तु, जाति आधारित लगाव राजनीतिक दिखावा खत्म होना चाहिए।समाज में जाति आधारित विद्वेष को ही नहीं विभेद को भी समाप्त करना जरूरी है। ताकि सद्भाव के साथ विकास को भी बल मिल सके। इस दिशा में सही काम करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित रैलियों को, सार्वजनिक प्रदर्शनों को और पुलिस अभिलेखों में जाति-आधारित उल्लेखों को प्रतिबंधित कर दिया है। खासतौर पर ऐसा निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक प्रदेश के बाद लिया है। गौर किये जाने योग्य है कि - जाति आधारित संगठनों और रैलियों की बाढ़ सी आ गई है। एक-एक जाति के अनेक संगठन बनने लगे हैं। ऐसे संगठन जब सड़कों पर उतरते हैं, तब इससे न केवल सार्वजनिक-व्यवस्था बल्कि राष्ट्रीय एकता भी प्रभावित होती है। किसी एक जाति के प्रति लगाव दर्शाने के लिए किसी अन्य जाति के लोगों को नीचा दिखाने की गलत परम्परा भी स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा हैं। जाति आधारित पोस्टर या सिर्फ गलियों में बल्कि अपने वाहनों पर भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में परस्पर भेद बढ़ता जा रहा है जिसे मिटाए जाने को मांग समय समय पर उठाई जाती रही है। सामाजिक विचारकों एवं चिंतकों की यह इच्छा है कि-जातिगत पोस्टरों एवं झंडों के ऊपर भी लगाम लगाई जाए। अफसोसजनक है कि- विशेष रूप से चुनाव के समयः जाति आधारित बैनरों बाढ़ आ जाती है। सरकार की मंशा सराहनीय है और इन दिशा निदेर्शों को पूर्ण रुप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। वाकई समाज से अपराध को मिटाने के लिए अपराधी की जाति देखना गैरवाजिब है। यह नहीं भूलना चाहिए कि- जाति आधारित भेदभाव आज भी कई जल हों, जगहों पर देखने को मिल जाता है। भेद भाव के उन बिंदुओं को खोज-खोज कर मिटाने में समाज की भलाई है।

कुत्तों की आक्रामकता का कारण उनका प्रजनन काल

गोरखपुर। प्रजनन काल के इस मौसम में कुत्तों की आक्रामकता में खासी वृद्धि होती जारही है जिससे बचाव, बंध्याकरण एवं रेबीज रोधी टीका करण का कार्य बाधित होता जा रहा है। अथवा पूर्वी रूप से रूप छे गया है। गुलरिहा में संचालित कार्य एनिमल वर्थ कंट्रोल सेंटर पर पिछले पखवाड़े से ताला लगा हुआ है। पुरानी ने पिछले नौ सितंबर से कमी करना बंद कर दिया है। निगम ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया था। लेकिन किसी भी फर्म ने इस दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। अब . नगर निगम का तीसरा आर एफ पी जारी किया गया है, जिसके तहत आगामी तीन अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं और चार को बिड खोली जानी है।

बताते चलें कि पिछले 15 दिनों में कुत्ता काटने की घटनाएं शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हैं। प्रतिदिन 250 से अधिक लोग जिला अस्पताल में रेबीज की लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। कुछ लोगो ने नगर निगम में शिकायत भी किया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। बताते चलें कि- शहर के विभिन्न हिस्सों में - (दाउदपुर, महेवा फलमंडी, बेतियाहाता, रुस्तमपुर, ट्रांसपोर्ट नगर, पांडेय हाता, मियां बाजार, छोटे काजीपुर

एबीसी सेंटर का संचालन करने वाली संस्था (कर्म) ने काम बंद कर दिया है। और नई फर्म के लिए टेंडर जारी किया गया है। उम्मीद है जल्द ही सेंटर का संचालन शुरू होगा।

डॉ.रोबिन चंद्रा
पशुकल्याण एवं चिकित्साधिकारी
नगर निगम, गोरखपुर ।

अलीनगर, रेती रोड़, हुमायूंपुर जमनालाल बजाज पार्क, पादरी बाजार, रसूलपुर, नंदानगर देवरिया बाईपास रोड सहित अनेक क्षेत्रों में) आवारा कुत्तों की वजह से आवागमन प्रभावित होता है। इससे कहीं अधिक संख्या में कुत्ते गलियों में डेरा जगाए हुए रहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुत्तों को पकड़ने एवं उनके बंध्याकरण की व्यवस्था ध्वस्त हो गई।

विदित हो कि राज्य सरकारने हाल होने कड़े कदम उठाते हुए कई दिशानिर्देश भी जारी किए- यदि सड़क पर घूमने वाला कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो नगर निगम द्वारा दस दिनों तक तत्काल एबीसी सेंटर में रखना होगा। इस दौरान उसका बंध्याकरण एवं रेबीज रोधी टीकाकरण करना अनिवार्य होगा। इन दिनों कुत्ते के स्वास्थ्य एवं व्यवहार की प्रतिदिन निगरानी की जाएगी।

एबीसी सेंटर से छोड़ने से पहले कुत्ते में माइक्रो चिप लगाना भी अनिवार्य होगा जिससे भविष्य में उसकी पहचान सुनिश्चित हो सके। यदि माइक्रोचिप लगे किसी भत्ते द्वारा दूसरी बार किसी शक्ति को काटा जाता है या ऐसी कोई घटना होती है और यह अप्रेरित उकसावा (बिना उकसावे का हमला) सिद्ध होता है तो ऐसे कुत्ते को आजीवन एबीसी सेंटर में रखा जाएगा।

पशु चिकित्साधिकारियों के अनुसार- सितंबर से अक्टूबर के बीच आक्रामकता का मुख्य कारण नर कुत्तों का प्रजननकाल होता है जिससे उनमें हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस समय मादा कुत्ता बच्चों को जन्म देती है जिससे उनकी आक्रामकता बढ़ जाती है। इसके अलावा तापमान का बदलाव भी उनकी आक्रामकता को प्रभावित करता है।

शैक्षिक गोष्ठी और प्रतियोगिताओं का आयोजन

अंमेठी। राजकीय हाईस्कूल मंगरौली में बृहस्पतिवार को मिशन प्रबोधन के अंतर्गत शैक्षिक गोष्ठी और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को परीक्षा की बेहतर तैयारी से जुड़े उपयोगी सुझाव दिए गए।

प्रधानाचार्य सरोज सिंह ने कहा कि कक्षा छह से 12 तक का पाठ्यक्रम ही प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव है। सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न इसी से जुड़े होते हैं। यदि विद्यार्थी इसे केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सफलता पाने का आधार मानकर पढ़ें तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।

गजल के फन विषयक कार्यशाला का आयोजन

गजल ने जिंदगी के हर पहलू को अपने में समेटा है: डॉ. आलम

सुलतानपुर । राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गत शनिवार को बाबू धनंजय सिंह स्मृति आंतरिक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उर्दू विभागाध्यक्ष डॉ. महमूद आलम ने 'गजल के फन' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि गजल ने जिंदगी के हर पहलू को अपने में समेटा है, यही कारण है कि इसे शायरी की अन्य विधाओं से अधिक शोहरत मिली है। डॉ. आलम ने बताया कि गजल में शायर जब इशारों में अपनी बात कहता है, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उर्दू की पहली गजल अमीर खुसरो ने लिखी थी। गजल इश्क के हजारों रूपों को प्रस्तुत करती है और जब शायर अपने दिल की बात कहता है, तो वह आपबीती से जगबीती बन जाती है।महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश कुमार त्रिपाठी ने गजल को भारत की सांस्कृतिक धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मों से गजल को निकाल देने पर वहां वीरानी छा जाएगी। कार्यक्रम का संचालन और आभार ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय ने किया। इस अवसर पर उप प्राचार्य प्रोफेसर निशा सिंह, आइक्यूएसी निदेशक प्रोफेसर इन्द्रमणि कुमार सहित महाविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सुरक्षित गर्भ समापन दिवस का आयोजन आज

सीतापुर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी 28 सितंबर को जिला महिला चिकित्सालय सहित विभिन्न सीएचसी पर सुरक्षित गर्भ समापन दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

इस मौके पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि इस मौके पर जिला महिला चिकित्सालय सहित सिधौली, ऐलिया, हरगांव, लहरपुर, बिसवां, कसमंडा, खैराबाद, पहला, महमूदाबाद, महोली, गोंदलामऊ एवं शहरी पीएचसी सदर बाजार पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है।

इस मौके पर प्रशिक्षित चिकित्सक लाभार्थियों को सुरक्षित गर्भ समापन की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में जपाइगो एवं आईपॉस संस्था द्वारा सहयोग किया जा रहा है।

'कॉफी विद कलेक्टर' कार्यक्रम का आयोजन

मुसाफिरखाना, अमेठी। नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शारदीय नवरात्रि के अवसर पर शुरु किए गए मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान की एवं मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल की अध्यक्षता में छात्राओं के संग 'कॉफी विद कलेक्टर' कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने प्रतिभाग कर महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार एवं समाज में समान अधिकार संबंधी सवाल पूछे जिसका उपरोक्त अधिकारीद्वय ने बड़े ही शालीनता के साथ धैर्यपूर्वक उत्तर दिया ।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक्स की याचिका की खारिज

महिलाओं के मामले में इंटरनेट मीडिया को रेगुलेट करने की आवश्यकता

▶ इंटरनेट मीडिया मनमाना नहीं हो सकता : हाई कोर्ट

नई दिल्ली/बेंगलुरू। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व मे ट्विटर) को कर्नाटक कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक तगड़ा झटका दिया है। एक्स कार्य की एक याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि- इंटरनेट मीडिया मनमाना नहीं हो सकता उसे भारत के कानून मानने होंगे। कोई भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म भारतीय बाजार को महज प्ले ग्राउंड नहीं मान सकता है। जहां नियमों और कानूनों की अनदेखी करते हुए जानकारी को प्रसारित की जा सके। इंटरनेट मीडिया को रेगुलेट किए जाने की आवश्यकता है। खासकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में। ऐसा नहीं होने पर संविधान में नागरिकों को दिए गए गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होगा।

एक्स ने अपनी याचिका में भारत के सख्त इंटरनेट नियमन को निशाना बनाया था। उसने केन्द्र सरकार के 'सहयोग पोर्टल की वैधता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून को (आईटी कानून को) तहत सरकारी अधिकारियों को सामग्री हटाने (टेक डाउन) का आदेश देने के अधिकार को चुनौती दी थी। गई थी। सहयोग पोर्टल एक ऑन लाइन प्लेट फार्म है जिसका उपयोग इंटरमिडिएटरी (बीच के सेवाप्रदाता) को सामग्री हटाने के आदेश जारी करने के लिए किया जाता है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकलपीठ ने आदेश में कहा है कि-

सहयोग पोर्टल एक सार्वजनिक हित का साधन है। यह नागरिक और इंटरमिडिएटरीज के बीच सहयोग का एक उदाहरण है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने की कोशिश करती है। इसकी वैधता पर सवाल उठाना इसके उद्देश्य को गलत साबित करना है। इस पर आपत्ति करना अनुचित है। कोर्ट ने आगे कहा कि-विचारों के आधुनिक मंच के रूप में इंटरनेट मीडिया को अराजक स्वतंत्रता की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है। इस क्षेत्र से सूचना नियमन न तो नया है और न ही अनोखा। महिलाओं के सम्मान की रक्षा और उनके विरुद्ध अपराधो को रोकने के लिए सामग्री कारेगुलेशन आवश्यक है।

स्वतंत्रता के साथ जुड़ी होती है गंभीर जवाबदेही

कोर्ट ने आजादी का मौलिक अधिकार देने वाले अनुच्छेद-19 के विषय में कहा कि यह अपने वादे में स्पष्ट है। लेकिन यह केवल नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का चाहर है। कोई याचिकाकर्ता जो इस देश का नागरिक नहीं है। इसके तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि- हमारे देश के क्ष-त्राधिकार में काम करने वाले प्रत्येक प्लेटफार्म को यह स्वीकार करना होगा कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है और पहुंच का विशेषाधिकार अपने साथ साथ जवाबदेही गंभीर कर्तव्य लेकर आता है।

लोगों की पहली पसंद बनता पीवीसी बाल पेपर

गोरखपुर। त्योहार के सीजन में लोग घरों को सजावट और साफ सफाई में लगे हुए है और पॉलिश की जगह लोगों का झुकाव दीवारों को पीवीसी शीट और वॉल पेपर से सजाने की ओर कुछ ज्यादा ही है। अलग-अलग रंगों और आकर्षक डिजाइन वाली पीवीसी पैनल न केवल देखने में खूबसूरत लगते हैं। बल्कि लंबे समय तक कमरों की रौनक श्री बढ़ाते हैं। बारिश के मौसम में सीलन की समस्या से भी निजात मिल जाती है। दुकानदारों की मानें तो पेंट की में तो पेंट की तुलना में पीवीसी शीट और वाल पेपर लगाना आसान और टिकाउ होता है।

महेवा मंडी के पास - इंटीरियर डेकोरेशन सामग्री के थोक विक्रेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि- इन दिनों पीवीसी शीत को मांग काफी बढ़ गई है। नयी वाले स्थानों पर बने मकान दुकान और प्रतिष्ठानों इसका अधिक प्रयोग हो रहा है। वाल पेपर भी लोग लगता रहे हैं। लेकिन नमी की वजह से यह जल्दी उखड़ जाते हैं उनकी तुलना में पीवीसी शीट टिकाऊ होने के कारण लंबे समय तक चलती है। मोहद्दीपुर के विक्रेता बताते हैं- पीवीसी की कीमत 40 रुपए प्रतिवर्ग फीट से शुरू होती है। डिजाइन और गुणवत्ता के हिसाब से दर बढ़ जाती है जबकि वाल पेपर की कीमत 19 मीटर रोल के हिसाब से 250 रुपए से लेकर तीन हजार रुपए तक होती है।

दुकानदार यह भी बताते हैं कि पेंट लगाने में अधिक समय और मेहनत लगती है जबकि पीवीसी से दीवारें कुछ ही घंटों में नई दिखने लगती है। ग्राहक सुविधा और स्टाइल दोनों चाहते हैं। इसलिए उसकी मांग बढ़ रही है। अधिकांश लोग मध्यम कीमत वाले विनाइल और प्रिंटेड वाल पेपर को पसंद करते हैं। होटल रेस्त्रां और दुकानों में थ्री डी डिजाइन वले शीट और वाल पेपर की मांग अधिक है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा अंतराष्ट्रीय नियमों के अनुसार-यह यह प्रतिबंधित है। कई बार ऐसे रंगों का प्रयोग पुराने आलू को ताजा और चमकीला दिखाने के लिए किया जाता है।

केमिकल युक्त आलू को बेचने के लिए सक्रिय

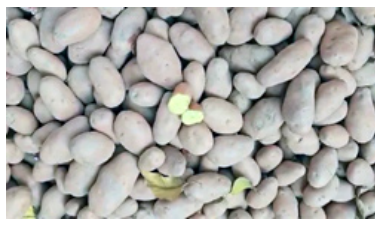

गोरखपुर। नवरात्रि के दौरान केमिकल युक्त आलू को बेचने के लिए सक्रिय हैं। हाल के दिनों में कर्ड ट्रकों से महेवा फल मंडी में केमिकल युक्त आलू बड़ी मात्रा में आ रहा है। ट्रकों से आए की बोरियां उतारने वालों (पल्लेदारों) की त्वचा केमिकल को चपेट में आ रही है जिससे उन्हें खुजली हो रही है। नती जन कई पल्लेदारों ने आल को बोरियां उतारने से मना कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम महेवा मंडी में पहुंच कर आलू की जांच की। चार दुकानों से आलू के लिए गए नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। कारोबारियों को निर्देश दिया ये गया है कि- वे रसायन युक्त आलू को न तो खरीदे और न ही बिक्री करें कुछ समय पहले बाराबंकी से आए आलू को रासायनिक रंगों से रंगे होने की पुष्टि भी हुई थी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि आयुक्त डा. सुधीर कुमार सिंह ने जब आलू मंगवाया। तो उन्हें रंग देख कर संदेह हुआ। जांच में आल पर लाल रंग का रसायन लगाए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद महेवा फल मंडी के समस्त आलू व्यापारियों को चेतावनी दी गई है। कुछ समय तक इस-चेतावनी का असर दिखा लेकिन नवरात्रि में लाल रंग रंगा आलू भारी बिक्री को देखते हुए व्यापारियों ने फिर से रासायनिक रंगों से रंगा आलू मंगाना शुरू कर दिया है।

कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है आलू:

कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू इस समय बाजार में आ रहा है। जो आलू खराब होने लगता है। उस पर मिलावट के कारोबारी लाल रंग का रसायन लगा देते हैं इससे आलू देखने में अच्छा लगता है और इसकी बिक्री आसानी से हो 'जाती है। कारोबारियों को यह आलू अन्य से कम दाम पर उपलब्ध होता है जिसे वे अधिक लाभ कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि - छिल्के पर लगा रसायन आलू के अंदर भीचला जाता है। इसके सेवन से बुखार और पेट खराब हो सकता है। लगातार मानत आलू खाने से कैंसर का खतरा भी बना रहता है। किडनी लीवर और अंग भी प्रभावित होते हैं।

शुभकामना-पुष्प

जन्मदिन की बधाइयाँ, करें पुत्र स्वीकार,
है सबकी शुभकामना, खुशियाँ मिलें हजार।।

बहुत-बहुत शुभकामना, तुमको प्रियवर आज,
हो प्रशस्त जीवन सुखद, सुन्दर साज समाज।।

जीवन भर मिलती रहें, खुशियाँ सदा अपार,
मात शारदे आपके, भरें ज्ञान भण्डार।।

शुभ सरिता बहती रहे, जीवन हो सत्संग,
घर आँगन खिलते रहें, प्रेम-प्रीति के रंग।।

धर्म-कर्म अध्यात्म का, सदा करें उत्थान,
लक्ष्य प्राप्ति हेतु अनवरत, बढ़े सौरभ प्रज्ञान।।

जीवन भर प्रज्ञान को, खुशियाँ मिलें अपार,
बुजुर्ग शुभ आशीष दें, बाँटे लाड-दुलार।।

उन्नति पथ बढ़ते रहो, स्वप्न करो साकार,
ईश्वर की कृपया रहें, खुशियाँ मिलें अपार।।

आज हुआ दो वर्ष का, हर्षित है प्रज्ञान।
दे रहे दुआएँ सभी, बनी रहे मुस्कान।।

- डॉ. सत्यवान सौरभ/डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत सरकार इस कार्य युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक राष्ट्रीय पहल

पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम का होगा आयोजन

गोरखपुर। देश के सर्वाधिक दुर्घटना वाले 100 जिलों में गोरखपुर- कुशीनगर और बस्ती भी शामिल हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी सूची में गोरखपुर मंडल के दो और बस्ती मंडल के एक समेत उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों को शामिल किया गया है। सूची में गोरखपुर जनपद 85 वें, कुशीनगर 86 वें, तथा बस्ती अंतिम पायदान यानी 100वें नंबर पर है। सूची में पहले पायदान पर छत्तीसगढ़ का रामपुर जिला है। मंत्रालय की सूची में शामिल इन जिलों में मार्ग दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम लागू किया जाएगा। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पहल पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम लागू करने की प्रक्रिया भी शुरूकर दी है।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भारत सरकार, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सड़क सुरक्षा मित्र से अवगत करा दिया गया है। परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के चिन्हित सभी 28 जनपदों को सूची भेजते हुए सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है

परिवहन आयुक्त के अनुसार- कार्यक्रम का संचालन जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति (डी. आर एस सी) के अधीन जिलावार किया जाएगा। इसके लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। माई भारत पोर्टल के साथ समन्वय स्थापित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य माई भारत पोर्टल प्लेटफार्म के माध्यम से 18 से 28 वर्ष के प्रशिक्षित युवाओं को जिला स्तर को सड़क सुरक्षा की कार्यवाहियों से जोड़ना है।

जाम का सबब बनते चौराहों पर सवारी भरते ऑटो रिक्शा

गोरखपुर। ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चौराहों पर यात्रियों को बैठाने के चक्कर में ऑटो चालकों ने आपाधापी मचा रखी है। जो जाम की समस्या का कारण बन जाती हैं। निर्धारित स्थान की बजाय चालक चौराहे के पास ही खड़ा कर रहे है जिससे व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रही है। बताते चलें कि शहर में 15 हजार से अधिक ऑटो और ई-रिक्शा का संचलन हो रहा है। इन वाहनों के लिए चौराहों से कम से कम पचास मीटर की दूरी पर खडा करने का नियम है। लेकिन इनका कमी अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

ऐसा ही एक दृश्य - गत सोमवार की सुबह विश्वविद्यालय चौराहे पर गोविवि तरफ जाने वाली लेन में ऑटो चौराहे के समीप खड़े थे। मोहद्दीपुर से आने वाली लेन में बसों के इंतजार करने के कारण ई-रिक्शा ऑटो की लंबी कतार लग गई 901 ऐसी ही पर देखने को मिलती है। रुस्तम घुट चौराहे पर यात्री बैठाने के चक्कर में 'चालक अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा कर देते हैं जिससे अक्सर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

एक मनमानी अंबेडकर चौराहे (सिविल कोर्ट के गेट)

शास्त्री चौराहे पर बने ऑटो स्टैंड के बजाय चालक चौराहे पर ही ऑटो खड़ा करती हैं जिससे बेतियाहाता जाने वाली लेन में अक्सर जाम लगा रहता है। अंबेडकर चौराहे पर जाने वाली बाई बेन में भी ऑटो खड़े होते हैं। इसी प्रकार सोनौली हाइवे पर धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचे गोरखनाथ की ओर 'जाने वाली बेन में भी ऑटो में यात्री बैठाने के कारण जाम लग जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन स्थानों पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है लेकिन इसका चालकों पर कोई असर नहीं पड़ता। कभी-कभी पुलिसकर्मी चालान काट कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते।

श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनी महाराजा अग्रसेन जयंती

गोरखपुर। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतिम दिन कार्यक्रम सोल्लासपूर्ण वातावरण में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। बीते सोमवार की सुबह महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको नमन करते हुए अपराह्न तीन बजे डी बी स्कूल बेनीगंज से शोभा यात्रा निकाली गई इसमें शामिल लोगों की आस्था देख स्थानीय लोग भावविभोर हो गए। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत सोमवार की सुबह नौ बजे राज्य सभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डा. राधा मोहन दास अग्रवाल' ने अग्रसेन तिराहे, बैंक रोड स्थित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर अग्रवाल भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय प्रकाश अग्रवाल सहित सैकड़े लोगों की उपस्थिति से माहौल भक्ति और उत्साह से सराबोर हो गया। दोपहर तीन बजे शोभा यात्रा का शुभारम्भ ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय प्रकाश, सचिव वेद प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्रीनाथ दास अग्रवाल समन्वयक आलोक अग्रवाल, संयोजक राजीव रंजन तथा सहसंयोजक अनूप अग्रवाल ने संयुक्त रुप से किया। महिला मंडल की अध्यक्ष मंजू अग्रवाल एवं अग्रवाल महिला समिति की अध्यक्ष शर्मिला अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन की आरती उतार कर शोभायात्रा का मंगलारंभ किया। श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा में शामिल होकर महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। शोभा यात्रा डीबी स्कूल से प्रारंभ होकर चरन लाल चौक, मानस टाकीज, आर्यनगर चौक, विजय चौक, बैंक रोड अग्रसेन तिराहे और बक्शीपुर चौक होते हुए अग्रवाल भवन पर समाप्त हुई। इस दौरान पूरे मार्ग पर जगह जगह शोभायात्रा का स्वागत किया गया इसके बाद शाम को सात बजे लघु नाटिका - यमराज की चिंता का मंचन किया गया।

▶ गगनभेदी नारों एवं प्रभात फेरी के बीच याद किए गए शहीद-ए-आज़म भगत सिंह

शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वक्ताओं ने भगत सिंह के सपनों को किया याद

गोरखपुर (जीकेबी)। ग्राम एकला बाजार से सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंच, गोरखपुर के तत्वाधान में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जयंती के अवसर पर ग्राम बाघागाड़ा पंचायत भवन के पास से शहीदे आजम भगत सिंह की मूर्ति बेतिया हाता चौराहे तक गाजा बाजा के साथ सैंकड़ो की संख्या में मोटर साईकिल और चार पहिया वाहनों तथा पैदल चलकर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें गांव और क्षेत्र के तमाम नौजवान, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह के बहुत सारे नारे जैसे इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, संप्रदायवाद म्मुर्दाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहें और भगत सिंह के साथ विभिन्न क्रांतिकारियों के भी नारे लगाए गए और क्रन्तिकारी गीत गाए।

इस अवसर पर शहीद भगत सिंह के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और बक्ताओं ने उनके सपनों को याद करते हुए बताया कि भगत सिंह देश को एक नए तरह की आजादी, जिसमें व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण बंद हो और सभी प्रकार के शोषण उत्पीड़न

जयंती पर गाए गए क्रांतिकारी गीत

खत्म किए जाने बातों पर जोर देते थे। वे समाजवादी भारत बनाने की बात करते थे । वह किसी भी तरह की चाहे विदेशी हो या अपने देश का किसी के द्वारा जुल्म, शोषण अत्याचार, ऊंच नीच भेद भाव के खिलाफ थे, और वह चाहते थे कि चाहे जिस धर्म सम्प्रदाय का हो सभी एक आसमान के नीचे खुली हवा में सांस ले सके । सूच्य है कि ग्राम एकला में पिछले दो-तीन वर्षों से शहीद भगत सिंह की जयंती और शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आज भगत सिंह जयंती के अवसर पर यह भी संकल्प लिया गया कि हम लोग भगत सिंह के सपनों के अनुसार नए समाज बनाने का प्रयास करेंगे।

मेडिडटेशन ब्रिजिंग: लॉ एण्ड कॉन्फलिक्ट का पूर्व उपराष्ट्रपति ने किया विमोचन

नई दिल्ली। प्रखर गूंज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित "Mediation: Bridging Law and Conflict Resolution" का लोकार्पण भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा जगत के प्रख्यात हास्य अभिनेता, पद्मश्री व नंदी पुरस्कार से सम्मानित कन्नेगंटी ब्रह्मानंदम जी, जिन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, की विशेष उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया। यह पुस्तक अपने विषय में अनूठी है और वैकल्पिक विवाद निवारण विशेषकर मध्यस्थता की भूमिका को गहराई से समझाती है।

लेखक सुरेंद्र सिन्हा, एक प्रख्यात अधिवक्ता हैं जिनके पास 27 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वे विभिन्न सरकारी संस्थानों, एंटी-करप्शन ब्रांच, केंद्रीय सतर्कता आयोग , नगर निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ वरिष्ठ परामर्शदाता और विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अनेक जटिल व उच्च-प्रोफाइल मामलों का संचालन किया है। अपने व्यापक विधिक अनुभव के आधार पर उन्होंने इस पुस्तक को तैयार किया है, जिसमें न केवल कानूनी पहलुओं का विश्लेषण है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण, सहानुभूति और संवाद की शक्ति को भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। "Mediation: Bridging Law and Conflict Resolution" केवल विधि व्यवसायियों के लिए ही नहीं, बल्कि छात्रों, मध्यस्थता के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों, प्रशासकों और आम पाठकों के लिए भी एक मार्गदर्शक है।

यह पुस्तक बताती है कि कैसे मध्यस्थता के माध्यम से लंबे और महंगे मुकदमों से बचकर, समय और संसाधनों की बचत की जा सकती है और साथ ही रिश्तों को भी संरक्षित रखा जा सकता है। लेखक का मानना है कि मध्यस्थता न्याय को केवल अंतिम निर्णय तक सीमित नहीं करती, बल्कि समझ और सहयोग के माध्यम से न्याय को अधिक मानवीय और व्यावहारिक बनाती है।

घूँघट की बगावत

28 सितम्बर 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

नवरात्रि, प्रसाद और पालन-पोषण: आस्था में विवेक का महत्व

नवरात्रि, भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह केवल नौ दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह भक्ति, संयम, स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। नवरात्रियों के दौरान भक्त अपने घरों और मंदिरों में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और भोजन तथा खान-पान पर विशेष ध्यान देते हैं। हलवा-पूरी, चने की दाल, फल और अन्य पारंपरिक व्यंजन इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इन व्यंजनों का स्वादिष्ट और पवित्र होना उन्हें एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनाता है। हालांकि, इस पवित्र परंपरा के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: क्या नवरात्रियों में बनाए जाने वाले ये व्यंजन केवल मानव उपभोग के लिए ही सुरक्षित हैं, या इन्हें हमारे पवित्र मित्र, जैसे गाय, को भी दिया जा सकता है? यह प्रश्न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

नवरात्रियों में हलवा-पूरी का प्रसाद मुख्य रूप से गेहूं के आटे, घी और चीनी से तैयार किया जाता है। इसके स्वाद और सुगंध से भक्त आनंदित होते हैं और इसे देवी की भक्ति का प्रतीक मानते हैं। हलवा-पूरी का आनंद लेना न केवल उत्सव का हिस्सा है, बल्कि यह पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। हालांकि, इसके स्वास्थ्य पहलू पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। इंसानों के लिए हलवा-पूरी सीमित मात्रा में ऊर्जा और संतोष प्रदान करती है। परंतु, अत्यधिक मात्रा में इसे खाना पाचन समस्याएँ, वजन बढ़ना और अन्य स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। नवरात्रियों के दौरान लोग अक्सर फल, हल्का सत्त्विक भोजन और दूध जैसी चीजों का सेवन करते हैं, ताकि शरीर और मन दोनों को शुद्ध किया जा सके। इसलिए, हलवा-पूरी का सेवन संयमित और सोच-समझकर होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या गाय को भी हलवा-पूरी दी जा सकती है। हिंदू धर्म में गाय को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे माता का दर्जा प्राप्त है और धार्मिक ग्रंथों में उनकी सेवा और संरक्षण का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन, गायों का पाचन तंत्र इंसानों से भिन्न होता है। वे मुख्य रूप से हरी घास, चारा, भूसा और अनाज पर निर्भर करती हैं। घी, चीनी और मैदा जैसी भारी और मीठी चीजें उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं। हलवा-पूरी में मौजूद अत्यधिक घी और चीनी उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इससे दस्त, अपच और अन्य जठरांत्र संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर संतुलन की आवश्यकता स्पष्ट होती है। नवरात्रियों का उद्देश्य न केवल आस्था और भक्ति है, बल्कि पशुओं और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व बनाए रखना भी है। श्रद्धा और सुरक्षा एक साथ चल सकते हैं। गायों के स्वास्थ्य के लिए हलवा-पूरी देना सही नहीं है, और उन्हें प्राकृतिक चारा, हरी घास और फल देना सर्वोत्तम विकल्प है। धार्मिक दृष्टि से, श्रद्धा का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपनी आस्था का पालन करते हुए भी विवेक का उपयोग करें। पारंपरिक दृष्टि से, नवरात्रियों में प्रसाद वितरण केवल मानव उपभोग तक सीमित होना चाहिए। ऐसा करने से धार्मिक आस्था का पालन होता है और पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहती है। कई मंदिर और धार्मिक स्थल इस संतुलन को बनाए रखते हुए अपने प्रसाद में केवल फल, हरी पत्तियाँ और सूखा अनाज देते हैं। इससे गायों को पोषण मिलता है और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपरा में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में उनका संरक्षण, सम्मान और सेवा विशेष रूप से उल्लेखित है। अगर हम नवरात्रियों में श्रद्धा और परंपरा का पालन करते हुए गायों के स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं, तो हम उनकी सुरक्षा और पालन-पोषण के सिद्धांतों के प्रति उत्तरदायी नहीं रह पाते। यह एक ऐसा मामला है जहाँ धर्म और विज्ञान का संतुलन आवश्यक है। शिक्षा और जागरूकता इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धार्मिक आयोजकों, मंदिरों और परिवारों को यह समझना आवश्यक है कि उनके द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक प्रसाद केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि अगर पशु उसमें सम्मिलित हैं, तो उनके लिए भी सुरक्षित होना चाहिए। स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि हलवा-पूरी गायों के लिए सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि गायों को इंसानों के खान-पान से अलग रखना उनके दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

सड़क हादसों की अनकही कहानी - सफेद हेडलाइट्स का सच

रात में तेज सफेद हेडलाइट्स सिर्फ.आँखों को नहीं, बल्कि जीवन को भी चौंधिया देती हैं। हर साल हजारों लोग इसके कारण हादसों में मरते हैं। यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे परिवारों की टूटी ज़िंदगी है। समाधान आसान है झ पीली हेडलाइट लगाएँ, तेज सफेद लाइट से बचें, सरकार नियम बनाए और आम लोग जागरूक हों। जनजन गुप्ता अभियान का संदेश साफ है: सफेद चमक नहीं, पीली दोस्ती चाहिए! सड़कें सुरक्षित हों, परिवार बचें और रात का सफर डर-मुक्त बने।

रात का सफर हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। अंधेरा, धुंध, बारिश झ ये सभी कारक सड़क पर जोखिम बढ़ाते हैं। लेकिन आज एक नया और अनदेखा खतरा हमारी सड़कों पर फैल रहा है झ वाहनों की तेज सफेद हेडलाइट्स। यह चमक केवल आँखों को चुभती नहीं, बल्कि कई बार सड़क हादसों का कारण बनती है।

भारत में हर साल लगभग डेढ़ लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं और लाखों लोग घायल होते हैं। इनमें से बड़ी संख्या रात के समय होती है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इन हादसों में सफेद हेडलाइट्स की तेज चमक की बड़ी भूमिका होती है। यह केवल तकनीकी समस्या नहीं है। यह परिवारों की टूटन, बच्चों की बेबसी और मात-पिता की पीड़ा का कारण बनती है। सफेद हेडलाइट्स की रोशनी पारंपरिक पीली रोशनी की तुलना में कहीं अधिक तेज होती है। इंसान की आँखें नीली-सफेद रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं। जब यह तेज रोशनी सीधे सामने से आती है, तो चालक और पैदल यात्री दोनों कुछ सेकंड के लिए अंधे हो जाते हैं। इसी पल में हादसा हो जाता है। बाइक सवार गिर जाते हैं, ट्रक या बस चालक वाहन पर नियंत्रण खो देते हैं और पैदल यात्री जीवन-मृत्यु की स्थिति में फँस जाते हैं। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी आँखें पहले से संवेदनशील होती हैं। सड़क हादसा केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। यह पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल देता है। बच्चे अपने माता-पिता से दूर हो जाते हैं, माता-पिता अपने बच्चों को खो देते हैं। कई परिवार हमेशा के लिए अधूरे हो जाते हैं। हादसों का आर्थिक प्रभाव भी बहुत बड़ा है। सड़क हादसों की वजह से हर साल भारत को ऋ८द्ध का लगभग तीन प्रतिशत नुकसान होता है। यह केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं है; यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा है।

दुनिया के कई विकसित देशों ने इस समस्या को पहले ही समझ लिया था। यूरोप, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हेडलाइट्स की चमक और रंग पर सख़्त नियम हैं। वहां पीली हेडलाइट्स को प्राथमिकता दी जाती है। यह केवल आँखों के लिए सुरक्षित नहीं है, बल्कि बारिश और धुंध में सड़क भी स्पष्ट दिखाई देती है। भारत में नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन ढीला है। वाहन निर्माता गाड़ियों में चमकदार हेडलाइट्स लगाते हैं और आम लोग अक्सर इस खतरे के प्रति जागरूक नहीं होते।

भारत में समस्या को और बढ़ाने वाले कारण हैं झ अनियंत्रित आफ्टर-मार्केट फिटिंग, यानी लोग बिना सोचे-समझे छएऊहेडलाइट्स लगवा लेते हैं; कानून का पालन न होना और सड़क सुरक्षा की अनदेखी; जागरूकता की कमी, जहां अधिकतर लोग नहीं जानते कि उनकी सफेद हेडलाइट दूसरों के लिए खतरा बन सकती है।

इस समस्या का समाधान मुश्किल नहीं है। जरूरत है कि सरकार, वाहन निर्माता और आम लोग मिलकर काम करें। सरकार को हेडलाइट्स की चमक और रंग (कलर टेम्परेचर) पर स्पष्ट मानक तय करने होंगे। 4300ङ से अधिक कलर टेम्परेचर वाली सफेद हेडलाइट्स पर रोक लगानी चाहिए। सड़क परिवहन विभाग को नियमित जांच और सख़्त कार्रवाई करनी होगी। वाहन निर्माता डिफॉल्ट रूप से सुरक्षित और पीली हेडलाइट्स लगाएँ और ब्राइटनेस के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता दें। साथ ही, जागरूकता अभियान बहुत जरूरी हैं। जनजन गुप्ता जैसे अभियान राष्ट्रीय स्तर पर फैलाए जाएँ। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर ह्लपीली हेडलाइट लगाओ झ ज़िंदगी बचाओह्व जैसे संदेश व्यापक रूप से साझा किए जाएँ। आम लोग खुद पहल करें, अपनी गाड़ी की हेडलाइट सुरक्षित बनाएं और अपने परिवार व मित्रों को भी जागरूक करें। जनजन गुप्ता अभियान का संदेश सीधा और असरदार है झ ह्लसफेद चमक नहीं, पीली दोस्ती चाहिए ह्व यह केवल नारा नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। यदि हम सब मिलकर इसे अपनाएँ, तो सड़कें सुरक्षित होंगी, परिवार हादसों से बचेंगे और रात का सफर डर-मुक्त होगा। सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन करना नहीं है, यह मानव जीवन की रक्षा का सवाल है। सफेद हेडलाइट जैसी छोटी चीज भी बड़े पैमाने पर मौत और दर्द का कारण बन सकती है। हर हादसा सिर्फ.एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की त्रासदी है।

भारत में यह समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। हर दिन सड़कों पर तेज सफेद लाइट से प्रभावित होकर दुर्घटनाएँ होती हैं। इनमें से कई हादसे जानलेवा होते हैं। बुजुर्ग, बच्चे और पैदल यात्री सबसे कमजोर होते हैं। तेज सफेद रोशनी उन्हें अपनी दिशा में निर्णय लेने का समय नहीं देती और हादसा अनिवार्य हो जाता है। कई परिवारों की ज़िंदगी इस वजह से हमेशा के लिए बदल जाती है। सड़क पर हुई दुर्घटना केवल सड़क हादसा नहीं है, यह सामाजिक त्रासदी है। बच्चे अपने माता-पिता से दूर होते हैं, माता-पिता अपने बच्चों से। कई परिवार कभी फिर पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते। इसके अलावा, हादसों के कारण इलाज और रिकवरी पर बहुत खर्च होता है, जिससे परिवार और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। दुनिया में कई देशों ने पहले ही कदम उठाए। यूरोप, जापान और अमेरिका में पीली हेडलाइट्स को प्राथमिकता दी जाती है। तेज सफेद हेडलाइट्स पर प्रतिबंध है। भारत में नियम हैं लेकिन उनका पालन कमजोर है। वाहन निर्माता चमकदार हेडलाइट्स को फैशन या मार्केटिंग के लिए बढ़ावा देते हैं, और लोग जागरूक नहीं हैं। इसका समाधान सरल है। सरकार को नियम बनाकर उनका पालन करना चाहिए। वाहन निर्माता सुरक्षित और पीली हेडलाइट्स लगाएँ। आम लोग खुद कदम उठाएँ और दूसरों को भी जागरूक करें। अभियान जैसे जनजन गुप्ता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं है, यह जिंदगी की रक्षा है। सफेद हेडलाइट्स जैसी छोटी-सी चीज कई जानों को खतरे में डाल सकती है। एक पल की तेज रोशनी कई परिवारों के लिए हमेशा के अंधकार का कारण बन सकती है। अगर हम सब मिलकर जागरूकता फैलाएँ और सुरक्षित हेडलाइट अपनाएँ, तो सड़कें सुरक्षित होंगी, हादसों से परिवार बचेंगे और रात का सफर भयमुक्त होगा। आज समय है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएँ, सरकार से नियम सख़्त कर-वाएँ, वाहन निर्माता अपनी ज़िम्मेदारी समझें और आम लोग जागरूक होकर बदलाव लाएँ। एक पल की चमक अगर जीवन का अंधकार बना सकती है, तो क्यों न उसी पल को जीवन और सुरक्षा की रोशनी में बदल दिया जाए। सड़कें सुरक्षित हों, हादसों से परिवार बचें और रात का सफर डर-मुक्त बने झ यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

– डॉ. सत्यवान सौरभ,

अभिव्यक्ति की आजादी ने समाज को दूषित किया.....

मिर्जापुर में सोशल मीडिया पर कमाई और व्यू के चक्कर में नवरात्रि में मां दुर्गा को अपशब्द कहने वाली महिला की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर मुहर लगा दिया है । चंद सिक्कों में धर्म बेच चुके ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो मुफ्त का पैसा मिले तो कुछ भी गा और खा सकते हैं, उसका कारण है कि अभिव्यक्ति की आजादी ने सब बर्बाद कर रखा है । मिजार्पुर जिला, जिसमें माँ दुर्गा का प्रसिद्ध तीर्थ रबिंध्याचल जीर अवस्थित है। यूपी बिहार का तो शायद ही कोई गाँव हो जहां से दस लोग हर नवरात्र में बिंध्याचल धाम न जाते हों। सनातन आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है वह स्थान, सो वहीं से गंदगी परोसने की शुरूआत की गई। उधर दूसरी घटना आजम खां करीब दो साल के बाद जेल से बाहर आ गए है मीडिया के मुताबिक इनकी रैली में भारत माता को डायन कहा गया था । अब ये भी नवरात्र में जमानत पर निकल आए , इन्हें अभी इलाज भी कराना है । जाहिर है राजनीति में हैं चर्चित तो रहेंगे ही । वैसे नेताओं का कुछ पता नहीं होता । लेकिन संभवतः आजम खां अखिलेश के साथ अब वैसे न रहें । अखिलेश उनके बाहर आने पर घबराए हुए हैं । वे जानते हैं कि आजम उनसे बहुत नाराज हैं । आजम ने खुद मीडिया से कहा कि दो साल में कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं आया । यूपी में 2027 में चुनाव हैं सो मिजार्पुर वाली घटना और आजम दोनको पर दांव खेला जा रहा । मैंने अलग अलग न्यूज चैनल के पेज पर टिप्पणियां पढ़ीं, उस फूहड़ औरत और आजम की गालीबाजी का समर्थन करने वालों की संख्या भी कम नहीं। उसके समर्थन में खड़े होने वालों में अधिकांश ऐसे होंगे जिनकी उनमें पूरी आस्था होंगी और पूरी आस्था से लड़ते है। पर राजनीति में अंधे हो चुके लोग जैसे अपनी समझ भी गिरवी रख चुके हैं। वे हिन्दू होते हुए भी मिशनिरियों की गुलामी कर रहे हैं। कभी कभी लगता है, एक साथ कितने मोर्चों पर लड़ना होगा निर्दोष हिन्दुओं को ? सत्तर वर्षों में पूरी तरह स्थापित हो चुका विदेशी चक्र प्रभावी तो है ही, दूसरे उसे ध्वस्त करने के प्रयास भी बहुत हल्के हैं। कैसे टूटेगा यह चक्र? केवल सरकारी प्रयासों से टूटता तो नहीं दिख रहा है। मुस्लिम वोटों पर आजम की पकड़ सहानुभूति में और भी मजबूत हो गई है । हालांकि भारत माता को डायन कहने का जो महापाप आजम ने किया है , उसका शाप तो उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ेगा । अब जबकि आजम खां करीब दो साल के बाद जेल से बाहर आए गए है । जाहिर है अखिलेश उनके बाहर आने पर घबराए हुए हैं । वे जानते हैं कि आजम उनसे बहुत नाराज हैं । यही वजह है कि अखिलेश उनसे मिलने अब रामपुर जाने वाले हैं । आजम ने खुद मीडिया से कहा कि दो साल में कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं आया । साफ है उनकी नाराजगी सपा के तमाम बड़े नेताओं से है । यह जरूर है कि फिलहाल आजम खां योगी विरोधी आंदोलनों को हवा दे सकते हैं । लेकिन बसपा में जाएंगे या नहीं , यह कहना अभी संभव नहीं ।

ओवैसी की तरह मुस्लिमों की राजनीति आजम खां के कितनी काम आएगी , यह समझने में थोड़ा वक्त लगेगा । आजम खां जिन गुनाहों में जेल गए , उन गुनाहों का शिकार होने वाले 80% मुस्लिम हैं । बड़ी बेशर्मी से उन्होंने गरीबों की जमीनें कब्जाई , बददुवाएं पाई । इधर ऐसे ही एजेंडे के तहत दो-तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के मिजार्पुर से वह कथित गायिका आरेस्ट हुई जो लम्बे समय से माँ दुर्गा के लिए के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए गीत गाती थी। उसके साथ उसका पति और आधा दर्जन और पकड़े गए। ऐसी विद्रोही स्त्रियां और असफल पुरुष स्वभाव से ही लालची होते हैं। इन महोदया के अभद्र होने के पीछे भी यही कारण था। ऐसी हरकतों से तनिक प्रसिद्धि और पैसे भी मिल जाती है, वह लोभ भी रहा होगा। खैर... वह पकड़ी गयी, और अब जेल में है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि उसने फलाँ के कहने पर यह सब किया है। कहने वाले ने उसे बताया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में महिसासुर का केस जीत चुका है, इसलिए मां दुर्गा को गाली देने में अब कोई खतरा नहीं। आप उस गायिका की तस्वीर देखें तो ही समझ जाएंगे कि उसका बौद्धिक स्तर इतना ही है। उसने सचमुच यह मान लिया होगा कि केस जीता जा चुका है, अब गाली देने में कोई खतरा नहीं..इसके बाद उसने यह भी बताया कि वे पति-पत्नी पहले ही ईसाई धर्म कबूल चुके हैं। कुछ लोगों को इसपर आश्चर्य हो रहा होगा, पर मुझे पहले से ही इस बात पर पूर्ण विश्वास था। आप यकीन कीजिये, यदि कोई व्यक्ति देवी देवताओं को गाली दे रहा है तो इसका एक ही अर्थ है कि वह धर्म छोड़ कर ईसाई हो चुका है। वह नाम से किसी भी हिन्दू वर्ग, जाति का दिख रहा हो, पर यकीनन वह अपना धर्म विदेशी पैसों पर बेंच चुका होता है। वह यदि भारतीय मूल के किसी भी सम्प्रदाय में होता तो देवी देवताओं को गाली नहीं दे रहा होता। आजम खां ऐसे समय में जेल से बाहर आए हैं जब इस्लामिक जेन जी को अचानक प्रोड्यूस किया गया है । 11 साल के दौरान देश जिन दंगों से मुक्त चला आ रहा था , अब उन्हें पूरी तरह प्रोजेक्ट करने की तैयारी नेताओं ने की है । जाहिर है आजम के पास काम की कमी नहीं होगी ।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

स्त्री-शक्ति केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी उसकी बराबरी की भूमिका हो

भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक महत्त्वपूर्ण संगठन के रूप में स्थापित है। 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित यह संस्था मूलतः पुरुष के लिए बनी थी। इसकी शाखाओं, अनुशासन और विचारधारा ने धीरे-धीरे भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा असर डाला। परन्तु जब हम महिलाओं की भूमिका की ओर देखते हैं, तो तस्वीर कुछ अलग मिलती है। आरएसएस के समानान्तर 1936 में जन्मी ह्लराष्ट्र सेविका समितिह्व ने ही स्त्रियों के लिए रास्ता खोला। आज जब संघ अपनी शताब्दी मना रहा है, तब इस यात्रा पर नजर डालना जरूरी है कि स्त्रियों की भागीदारी कहाँ से शुरू हुई और 2025 तक वह किस मुकाम तक पहुँची।

शुरूआती दौर: 1925 से 1936

संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई। यह संगठन अनुशासन, परेड, शाखा और राष्ट्रवाद पर आधारित था। लेकिन इसकी संरचना पुरुष प्रधान रही। हेडगेवार स्वयं मानते थे कि स्त्रियों को अलग मंच चाहिए, क्योंकि उस समय के सामाजिक परिवेश में स्त्रियों का सीधे पुरुष शाखाओं में आना सहज नहीं माना जाता था। इसी पृष्ठभूमि में 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर ने विजयादशमी के दिन वर्धा में ह्लराष्ट्र सेविका समितिह्व की स्थापना की। हेडगेवार ने भी इस पहल का स्वागत किया और सुझाव दिया कि महिलाएँ अपनी संस्था चलाएँ, ताकि वे अपनी शक्ति, संस्कृति और नेतृत्व को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकें। इस तरह महिलाओं की भागीदारी औपचारिक रूप से शुरू हुई।

सेविका समिति की स्थापना और शुरूआती संघर्ष

1939 में पहली बार समिति ने प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया। धीरे-धीरे अलग-अलग प्रांतों में इस-की शाखाएँ बनने लगीं। समिति का उद्देश्य केवल राष्ट्रवादी विचार फैलाना नहीं था, बल्कि स्त्रियों में ह्यमातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्वह्व (मातृत्व, कर्तृत्व, नेत्रृत्व) जैसे गुणों का विकास करना भी था। इसमें शारीरिक प्रशिक्षण, योग, गीत, खेल, अनुशासन और समाज सेवा शामिल किए गए। आजादी के आंदोलन में भी समिति की महिलाओं ने परोक्ष रूप से भूमिका निभाई। परन्तु उनकी गतिविधियाँ मुख्यतः सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों तक सीमित रहीं।

1940 से 1970 का दशक: विस्तार की ओर

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में समिति का नेटवर्क बढ़ा। लक्ष्मीबाई केलकर की मृत्यु (1978) तक संगठन कई राज्यों में फैल चुका था। उनके बाद सरस्वती आपटे प्रमुख संचालिका बनीं। इस समय तक शाखाओं की संख्या हजारों में पहुँच गई थी। समिति का जोर महिला शिक्षा, संस्कार, और सेवा परियोजनाओं पर रहा। आपातकाल (1975झ77) में समिति से जुड़ी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शनों में भी भाग लिया। इस दौर ने उन्हें राजनीतिक रूप से अधिक सचेत और सक्रिय बनाया।

1980-2000: आधुनिकता और परम्परा का संगम

90 के दशक में जब भारतीय राजनीति में भाजपा और संघ परिवार का प्रभाव बढ़ने लगा, तो महिलाओं की भागीदारी भी चर्चा में आने लगी। समिति ने इस समय शहरी और पेशेवर महिलाओं तक पहुँच बनाने की कोशिश की। महिला शिक्षिकाएँ, चिकित्सक और नौकरीपेशा स्त्रियाँ समिति के कार्यक्रमों से जुड़ने लगीं। 1994 में उषाताई चाटे और 2006 में प्रमिलाताई मेढे प्रखर नेतृत्व के रूप में सामने आईं। इन नेताओं ने महिला शाखाओं को आधुनिक मुद्दों—जैसे कामकाजी महिलाओं की चुनौतियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार में संतुलन—से जोड़ा।

2012 से आगे: शांथक्का का नेतृत्व

2012 में वेंकट्रामा शांता कुमारी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से ह्लशांथक्काह्व कहा जाता है, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका बनीं। उनका जन्म 1952 में हुआ और वे लंबे समय से संघ परिवार के कार्य में सक्रिय थीं। उनके नेतृत्व में समिति ने अपना विस्तार और तेज किया। आज समिति के पास चार से पाँच हजार शाखाएँ हैं, जो लगभग 800 से अधिक जिलों में फैली हुई हैं। यद्यपि सटीक आँकड़े संगठन सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन अनुमान है कि लाखों महिलाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ी हुई हैं। समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, छात्रावास और महिला सशक्तिकरण परियोजनाएँ चला रही है। शहरी महानगरों में भी इसकी शाखाएँ सक्रिय हो रही हैं।

संघ और महिला प्रश्न

संघ के भीतर महिलाओं को औपचारिक सदस्यता या नेतृत्व स्थान नहीं दिया गया है। आरएसएस की शाखाएँ केवल पुरुषों के लिए ही हैं। महिलाएँ केवल समिति के माध्यम से संघ के विचारधारा संसार का हिस्सा बनती हैं। आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था महिलाओं को मुख्यधारा से बाहर रखती है। वे पुरुषों के बराबर निर्णयकारी पदों पर नहीं पहुँच पातीं। परन्तु समर्थकों का मत है कि अलग संगठन होने से महिलाएँ स्वतंत्र रूप से नेतृत्व और गतिविधियाँ विकसित कर पाती हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार कहा है कि महिलाओं की भागीदारी ह्लप्राकृतिक रूप सेह्व बढ़ रही है। परन्तु अब भी नेतृत्व संरचना में असमानता साफ दिखाई देती है।

वर्तमान स्थिति (2025)

संघ अपनी शताब्दी मना रहा है। उसके लगभग 83,000 शाखाएँ देशभर में सक्रिय बताई जाती हैं। वहीं राष्ट्र सेविका समिति की शाखाएँ भी लगातार बढ़ रही हैं। समिति अब गाँवों के साथ-साथ महानगरों में भी काम कर रही है। इसके प्रशिक्षण वर्गों में स्कूली छात्राओं से लेकर पेशेवर महिलाएँ तक भाग ले रही हैं। 2025 में समिति का चेहरा परम्परा और आधुनिकता का मिश्रण है—जहाँ एक ओर मातृत्व और परिवार आधारित मूल्य हैं, वहीं दूसरी ओर समाज सेवा और महिला नेतृत्व के अवसर भी हैं। समिति ने लाखों महिलाओं को संगठित कर आत्मविश्वास और सामूहिकता दी। शिक्षा, सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समाज पर ठोस असर पड़ा। महिलाओं को नेतृत्व और प्रबंधन का अवसर मिला। महिलाएँ संघ की मुख्य धारा (आरएसएस) में निर्णयकारी भूमिकाओं से बाहर रहीं। संगठन का वैचारिक ढाँचा महिलाओं को परम्परागत भूमिकाओं तक सीमित करता है। आधुनिक नारीवादी विमर्श से समिति का दृष्टिकोण टकराता है, क्योंकि वह स्वतंत्रता और समानता की बजाय मातृत्व और संस्कृति पर जोर देती है। सितंबर 2025 में आयोजित व्याख्यानमाला के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (फ्रर) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी समाज और राष्ट्र निर्माण में पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। व्याख्यानमाला में यह भी कहा गया कि 2025 का भारत उस मुकाम पर खड़ा है, जहाँ महिला नेतृत्व केवल रपूरकर नहीं बल्कि रनिर्णायकर भूमिका निभा रहा है। वक्ताओं ने यह भी जोड़ा कि आधुनिक शिक्षा, तकनीक और आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में महिलाएँ जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, संघ परिवार को भी उसी अनुरूप अपनी संरचना और कार्यपद्धति को और खुला बनाना होगा। व्याख्यानमाला में अन्य वरिष्ठ कार्यकताओं और विचारकों ने भी महिला नेतृत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्र सेविका समिति की महिलाएँ दशकों से शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में काम कर रही हैं। यह तर्क दिया गया कि यदि 1925 में संघ की नींव रखी गई थी, तो उसी दशक में महिलाओं के लिए समानांतर संगठन की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं की उपस्थिति को शुरूआत से ही महत्वपूर्ण माना गया। 1925 से 2025 की यात्रा दिखाती है कि संघ की विचारधारा से प्रेरित महिलाओं ने अपना अलग संगठन खड़ा कर लिया और उसे राष्ट्रीय स्तर तक फैलाया। लक्ष्मीबाई केलकर से लेकर शांथक्का तक यह सिलसिला निरंतर चला है। आज जब भारतीय समाज में महिलाएँ राजनीति, शिक्षा, व्यवसाय और सेना तक में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, तब यह सवाल और महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि—क्या भविष्य में महिलाएँ सीधे संघ की शाखाओं और नेतृत्व में भी शामिल होंगी, या वे हमेशा समानान्तर संगठन तक ही सीमित रहेंगी ?संघ की शताब्दी महिलाओं की इस यात्रा का पड़ाव भी है—एक यात्रा जिसमें परम्परा, अनुशासन, सेवा और नेतृत्व का संगम है, लेकिन समानता और सहभागिता की चुनौती अब भी शेष है।

-प्रियंका सौरभ

सितंबर 2025 में आयोजित व्याख्यानमाला के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी समाज और राष्ट्र निर्माण में पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि स्त्री-शक्ति केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी उसकी बराबरी की भूमिका होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि मातृशक्ति के बिना राष्ट्र अधूरा है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि भारतीय संस्कृति में नारी को सदा पूजनीय और निर्णायक स्थान दिया गया है, इसलिए संघ परिवार की शाखाओं और गतिविधियों में महिलाओं का सक्रिय योगदान भविष्य की दिशा तय करेगा।

सोनम वांगचुक: दिलचस्प है एक समाजसेवी की आंदोलनजीवी बनने तक की यात्रा

सोनम वांगचुक की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक समय का नवोन्मेषक और समाजसेवी धीरे-धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विदेशी प्रभाव के चलते व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। लद्दाख की जनता को यह समझना होगा कि असली समाधान हिंसा और विदेशी फंडिंग से नहीं, बल्कि संवाद और संवैधानिक ढांचे के भीतर ही संभव है।

लद्दाख, अपनी शांत और सौम्य संस्कृति के लिए पहचाना जाता है, लेकिन वहां अशांति और असंतोष पनपाने की कोशिश की गयी। इस परिदृश्य के केंद्र में हैं सोनम वांगचुक। यह वही नाम है जो कभी शिक्षा सुधार और पर्यावरणीय नवाचार का प्रतीक था, पर आज शांति और व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है।

हम आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की प्रारंभिक छवि प्रेरक रही है। एएउटडछ के माध्यम से उन्होंने शिक्षा को लद्दाख की स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ा और आइस स्तूपा जैसी तकनीक ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। लेकिन 2019 के बाद, जब लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिला, उनका रुख धीरे-धीरे बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले नई दिल्ली का समर्थक माना जाता था, वही अब सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोलने लगा।

सोनम वांगचुक ने लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी के नाम पर बार-बार अनशन और आंदोलन किए। परंतु यह भी तथ्य है कि उनके आंदोलनों ने स्थानीय युवाओं में असंतोष को हवा दी। हाल ही में हुई हिंसा में चार निर्दोष जानें गईं, सैकड़ों घायल हुए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा। यह सब तब हुआ जब वांगचुक उपवास पर थे और उन्होंने कई बार ह्लउकसाने वालेह्व बयान दिए। सवाल यह उठता है कि यदि आंदोलन केवल शांतिपूर्ण था, तो यह हिंसा क्यों और कैसे हुई? सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सोनम वांगचुक के एनजीओ एएउटडछ और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स पर विदेशी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। केंद्र सरकार ने उनके एनजीओ का ऋफ्रअ लाइसेंस रद्द किया और उइक जांच शुरू की। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि उनके अभियानों को बाहरी शक्तियों से भी समर्थन मिल रहा था। जब राष्ट्रविरोधी तत्व देश की सीमाओं और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर गड़ाए हुए हों, तब इस तरह की विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियाँ गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्न खड़े करती हैं।

देखा जाये तो लद्दाख का भौगोलिक महत्व किसी से छिपा नहीं। चीन और पाकिस्तान से घिरी इस संवेदनशील भूमि में किसी भी तरह की अस्थिरता सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। ऐसे में यदि कोई नेता युवाओं को भड़काए, सरकारी संस्थानों पर हमला करवाए और हिंसा के बाद खुद को ह्लशांति दूतह्व बताने लगे, तो उसकी मंशा पर संदेह स्वाभाविक है। सोनम वांगचुक का यह कहना कि ह्लजेल में बंद वांगचुक, आजाद वांगचुक से ज्यादा खतरनाक होगाह्व दरअसल उनकी उसी मानसिकता को दर्शाता है जिसमें वह खुद को कानून से ऊपर मानने लगे थे। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, परंतु जब असहमति हिंसा, विदेशी प्रभाव और संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने का माध्यम बन जाए, तब उसे बर्दाश्त करना देशहित के खिलाफ होगा। हम आपको यह भी बता दें कि कुछ राजनीतिक नेताओं ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर आलोचना की है, परंतु यह बयानबाजी भी राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित लगती है। वास्तविकता यह है कि केंद्र ने कई दौर की बातचीत का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आंदोलनकारी समूह बार-बार शर्तें बदलते रहे। हिंसा के बाद यह साफ हो गया कि मामला केवल ह्लछठी अनुसूचीह्व या ह्लराज्य का दर्जाह्व भर का नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की रणनीति है।

देखा जाये तो सोनम वांगचुक की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक समय का नवोन्मेषक और समाजसेवी धीरे-धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विदेशी प्रभाव के चलते व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। लद्दाख की जनता को यह समझना होगा कि असली समाधान हिंसा और विदेशी फंडिंग से नहीं, बल्कि संवाद और संवैधानिक ढांचे के भीतर ही संभव है। आज जब लद्दाख की धरती पर शांति सबसे बड़ी आवश्यकता है, तो किसी भी व्यक्ति, चाहे उसकी पिछली छवि कितनी भी उज्ज्वल क्यों न रही हो, उसको कानून से ऊपर मानना राष्ट्र और क्षेत्र दोनों के लिए हानिकारक होगा। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी इसी व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है। हम आपको यह भी बता दें कि सोनम वांगचुक को राजस्थान के जोधपुर कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया है।

राष्ट्र संस्कृति से साक्षात्कार कराता पं. दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन

भारतीय राजनीति के वृहदाकाश में दैदीप्यमान पं. दीनदयाल उपाध्याय अपने राष्ट्रीय विचारों और प्रखर चिंतक, विचारक के तौर पर लब्धप्रतिष्ठित हैं। सनातन हिन्दू संस्कृति के मुखर पक्षधर और तदानुरुप रीति-नीति के आधुनिक राजनीतिक प्रवर्तकों की अग्रगण्य पंक्ति में उनकी गिनती होती है। पंडित जी ने केवल विचार ही नहीं दिए..अपितु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के माध्यम से विचारों को धरातलीय रूप भी दिया। एकात्म मानव दर्शन और अन्त्योदय जैसे मूल्य जनसंघ से होते हुए वर्तमान भाजपा की नीतियों में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। पण्डित जी विचारकों में प्रतिष्ठित व सुशोभित होने के साथ-साथ ही चिन्तन और दर्शन के बहुआयामी लोकल्याणकारक मान-बिन्दुओं के द्वारा नूतन प्रस्थापनाएँ करते हैं। साथ ही वैचारिक और कार्य स्तर पर कई सारी भ्रामक, अहितकारी रूढ़ियों को तोड़ते हुए भारतीयता के अनुरूप मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके विचार एवं दर्शन के विविध रुप हैं जिनमें उनका राजनीतिक दर्शन भी अपने आप में अनूठा है। उनके राजनीतिक दर्शन के मूल में भी राष्ट्र, संस्कृति, धर्म, उच्च आदर्श और समाज है। वे स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं कि राजनीति राष्ट्र के लिए ही होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की संकीर्णता या स्वार्थ प्रेरित हित लाभ के दृष्टिकोण-अराष्ट्रीय प्रवृत्ति एवं भारत की राष्ट्रीयता के लिए एक प्रकार का खतरा ही हैं। वे राजनीतिक शुचिता व राजनीति, दल, विचारधारा के मूल में राष्ट्रोन्नति और जनकल्याण को ही रखते हैं। येनकेन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति , अवसरवादिता और मूल्यों से पृथक राजनीति को तिलाञ्जलि देते हैं।

पं. दीनदयाल उपाध्याय एक श्रेष्ठ चिंतक-विचारक होने के साथ सजग थे। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व परिदृश्य में गहरा हस्तक्षेप करने वाली विचारधाराओं का गहन अध्ययन किया था। भारतीय दृष्टि के आधार पर उनका विश्लेषण और मीमांसा की थी।वे भारतीय राजनीति और वैश्विक राजनीति में अपना प्रभाव रखने वाली विचारधाराओं की तात्विक समीक्षा करते हुए उनका नीर-क्षीर विवेचन करते हैं। साथ ही स्वातन्त्र्योत्तर काल के उपरान्त पश्चिमी प्रभाव से ग्रस्त राजनीतिज्ञों की स्वदेशी की ओर न देखकर पश्चिम के अन्धानुकरण की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। पश्चिमी अन्धानुकरण की प्रवृत्तियों को पंडित जी भारत और भारतीयता के लिए आत्मध्वन्सात्मक बतलाते हैं। उनके मतानुसार आधुनिक पाश्चात्य देशों का उदय केवल पाँच सौ से सात सौ वर्षों की अवधि के पूर्व ही हुआ है, किन्तु भारत हजारों वर्षों से आसेतु हिमालय की भाँति एक उत्कृष्ट राष्ट्र के रूप में अवस्थित है। अतएव वे पाश्चात्य देशों की कसौटी और उनके निष्कर्षों पर भारत के आँकलन और अनुकरण करने को न्यायसंगत नहीं मानते हैं। दीनदयाल जी का मानना था कि जो हमारा है उसे समयानुकूल बनाया जाए तथा जो विदेशी है, उसे राष्ट्रानुकूल बनाया जाए। वे भारतीय समाज में केवल विदेशी होने के कारण श्रेष्ठताबोध और भारतीय होने के कारण उसे उपेक्षित और नकारने की दुष्प्रवृत्ति का विरोध करते हैं।

चूँकि राजनीतिक अन्धानुकरण के चलते स्वातंत्र्योत्तर भारत में पराजयबोध, हीनभावना की व्याप्ति अकादमिक स्तर पर क्रमशः स्थापित की गई। इसलिए वे इस पर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए कहते हैं - स्वत्व एवं स्वाभिमान का मेरुदण्ड सीधा तना न हो तो विश्व में भौतिक दृष्टि से बलशाली, प्रभावशाली,विजयशाली तथा वैभवशाली माने जाने वाले राष्ट्रों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति बल पकड़ती है। अपने पिछड़े और दरिद्र समाज से लज्जा आने लगती है। यह अनुसरण बड़ी बातों से लेकर छोटी-छोटी दैनिक बातों तक छनता चला आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विभिन्न विचारधाराओं और पश्चिमी व्यवस्थाओं को लेकर उनका गहन अध्ययन रहा है। वे व्यापक शोध एवं विश्लेषण के उपरान्त निष्कर्षतः यह कहते हैं कि -पश्चिम की नकल ह्यमॉडर्नह्व होने का प्रमाण बन गया है। यह चहुँमुखी अनुकरण ठीक नहीं, क्योंकि पश्चिमी चिन्तन और व्यवस्था मानव कल्याण में असफल रही है। आगे वे मैकॉले शिक्षा प्रणाली और उसके दुष्प्रभाव पर कहते हैं झ ह्लकिसी ने स्वदेशी पर जोर दिया तो उसे असभ्य

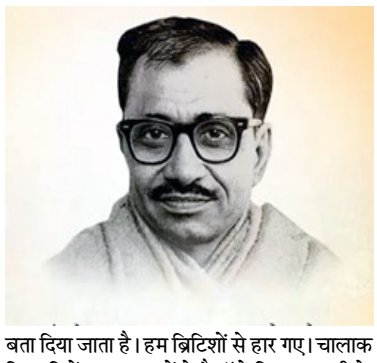

बता दिया जाता है। हम ब्रिटिशों से हार गए। चालाक मिशनरियों तथा शासकों ने मैकॉले शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हमारे मन में अनेक बीज बो दिए। तब से हमारे शिक्षितों में और उनकी देखादेखी समाज के अन्य लोगों में भी पाश्चात्यों के अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई है। स्वतन्त्रता के बाद तो वह निरंकुश हो गई है।

वे मार्क्स के दर्शन के पूर्णतः भौतिकवादी होने के सिद्धांत को अनुपयुक्त मानते हैं जिसके उदाहरण के तौर पर वो रूस, चीन के क्रूर प्रकरणों का विश्लेषण करते हैं। वहीं पंडित जी समाजवाद और लोकतान्त्रिक समाजवाद के द्वारा मनुष्य की स्वतन्त्रता की समाप्ति और समाजवाद के द्वारा मानवीय जीवन में राज्य के वर्चस्व को भी अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि 'लोकतान्त्रिक समाजवाद' जैसी कोई चीज नहीं है, शब्द भर है। क्योंकि समाजवाद लाने में लोकतन्त्र की हत्या करनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने पूँजीवादी व्यवस्था को भी मानव कल्याण के लिए असफल माना है। इन सबका हल सुझाते हुए वे कहते हैं – ह्लविश्व की समस्याओं का हल समाजवाद पूँजीवादी लोकतन्त्र नहीं, वरन- हिन्दूवाद है। यही एक ऐसा जीवनदर्शन है जो जीवन का विचार करते समय उसे टुकड़ों में नहीं बाँटता, अपितु सम्पूर्ण जीवन को इकाई मानकर उसका विचार करता है। वे इसे हिन्दुत्व और मानवता के तौर पर स्वीकार किए जाने की बात करते हुए स्पष्ट कहते हैं कि यही भारत की आत्मा के अनुरूप व जनमानस में उत्साह को सञ्चारित करेगा। साथ ही विभ्रान्ति के चौराहे में खड़े विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगा। पंडित जी राष्ट्र को जीवमान इकाई मानते हुए कहते हैं किझ ह्लएक भूमि विशेष में रहने वाले लोगों का, जिनके हृदय में मातृभूमि के प्रति असंदिग्ध श्रद्धा का भाव हो, जिनके जीवनादर्शों में साम्य हो, जीवन के प्रति स्पष्ट दृष्टि हो, शत्रु-मित्र समान हों। ऐतिहासिक महापुरुष एक हों; इन सबसे राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके विपरीत आक्रान्ता से इसलिए सहानुभूति रखना कि वे हम-मजहब हैं, अराष्ट्रीय प्रवृत्ति है।

इसी तरह वैश्विक राजनीति और भारतीय परिदृश्य में राष्ट्रवाद सर्वदा चर्चित रहता है, भारत की वामपंथी विचारसरणी, सिद्धांत विहीन दल- भारतीय राष्ट्रवाद – राष्ट्रीय विचारों को प्रायः हिटलर, मुसोलिनी से जोड़कर लाँछित करने लगते हैं। जबकि यह सर्वज्ञात तथ्य है कि भारत की राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के कारण ही स्वातन्त्र्य यज्ञ सफल हुआ था, अन्यथा स्वतन्त्रता असंभव सी थी। जोकि समस्त क्षेत्रों की चैतन्यता के फलस्वरूप मिली। पण्डित जी राष्ट्रवाद के सन्दर्भ में विस्तृत व्याख्या करते हुए कहते हैं यूरोपीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद में अन्तर है। यूरोपीय चिन्तन पारस्परिक संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है। जबकि भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म संघर्ष में नहीं हुआ है, अपितु सभ्यता के आरम्भ से ही भारत सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है ; जिसमें कई राजनैतिक सत्ताएँ थी किन्तु राष्ट्र एक था। भारत का राष्ट्रीय विचार न तो विस्तारवादी है, न ही साम्राज्यवादी और आक्रमणशील बल्कि भारतीय विचार वसुधैव कुटुम्बकम पर आधारित है जो प्राणिमात्र के प्रति कल्याण का भाव रखता है।

भारतीय विचार की तुलना पर वे कहते हैं पश्चिम के राष्ट्रवाद से भारत के विचार की तुलना करना ही गलत है। पश्चिम ने द्वैत के आधार पर संघर्ष का नगाड़ा बजाया और भारत ने अद्वैत के आधार पर एकात्म की बाँसुरी बजायी। दोनों वाद्य होते हुए भी दोनों की स्वरलहरियों में भारी अन्तर है। इस भेद को समझकर हमें राष्ट्रवाद का विचार करना चाहिए।

स्पष्ट है जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहां वे 'राष्ट्रीयता' को ही संबोधित करते हैं। आगे पंडित जी वे भूमि, जन, संस्कृति के संघात से राष्ट्र के निर्माण की बात कहते हैं। उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति का अभिप्राय ही हिन्दू संस्कृति है।

भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों गुजरात के भावनगर में कहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अन्य देशों पर निर्भरता है और जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ज्यादा राष्ट्रीय विफलता बढ़ेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य बाहरी ताकतों पर नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। आत्मनिर्भरता देश के सभी समस्याओं का समाधान है और यही राष्ट्रीय सौभाग्य और विकास की कुंजी है।

इससे साफ है कि 2025 की अंतिम तिमाही से पहले चले अंतरराष्ट्रीय दांवपेचों के दृष्टिगत प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को आगाह कर दिया है कि जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ज्यादा राष्ट्रीय विफलता होगी। ऐसा कहकर उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तरफ तो उन्होंने चीन से आयात पर और अमेरिका को निर्यात पर या ऐसे ही अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए सोच और साधन दोनों बदलने का आह्वान किया है।

वहीं, दूसरी तरह विदेशी बहु समझी जाने वाली कांग्रेस नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी और उनके पुत्र-पुत्रियों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विदेशी तिकड़मों से भी सावधान रहने के इशारे किए हैं, क्योंकिः उनका मुस्लिम प्रेम, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका प्रेम और राष्ट्रविरोधी ताकतों को सियासी संरक्षण देश के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। चूंकि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और सोनिया गांधी-प्रियंका गांधी क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा के सांसद हैं। इसलिए इनकी हर कोशिशों पर देश-दुनिया की नजर रहती है। प्रधानमंत्री मोदी की मानें तो किसी भी मामले में विदेशी निर्भरता से राष्ट्रीय स्वाभिमान को नुकसान पहुंचता है। जब देश अपनी जरूरतों के लिए बाहरी देशों पर निर्भर होता है, तो उसका स्वाभिमान कमजोर पड़ता है। देश का विकास और फैसले बाहरी ताकतों के प्रभाव में आ जाते हैं, जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकते हैं। वहीं विदेशी निर्भरता से आर्थिक नुकसान और अस्थिरता पैदा होती है। विदेशी निर्भरता से देश की आर्थिक सुरक्षा कमजोर होती है। वैश्विक बाजारों या विदेशी साधनों पर निर्भरता से आर्थिक संकट आने पर देश प्रभावित होता है, जिससे विकास रुक सकता है। विदेशी निर्भरता से विकास भी बाधित होता है। आत्मनिर्भरता की कमी के कारण देश अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाता और उद्योग, तकनीक, और नौकरियों का विकास रुक जाता है। इससे राष्ट्रीय विकास की गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा, विदेशी निर्भरता से रणनीतिक खतरा भी बढ़ता है। सुरक्षा और महत्वपूर्ण संसाधनों में विदेशी निर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर होती है। आपातकाल में या भू-राजनीतिक तनाव में यह बड़ी समस्या बन सकती है। यही वजह है कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई तरीकों और नीतियों पर काम कर रहा है। एक ओर भारत स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दे रहा है, जिस-के तहत घरेलू उत्पादन पर जोर देने से जहां आयात कम होगा, वहीं देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना जरूरी है। वहीं, दूसरी ओर भारत स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत नई तकनीकों और नवाचार को अपनाकर भारत को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम तेज की जा रही है, जिससे रोजगार निर्माण और आर्थिक विकास भी होगा। सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी मजबूत करने पर फोकस कर रही है। इससे अनुसंधान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश से भारत अपनी तकनीकी निर्भरता घटा रहा है। वहीं कौशल विकास के द्वारा युवाओं को कौशल शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के साथ-साथ उद्यमिता के लिए तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। वहीं, कृषि और ग्रामोद्योगों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने, उर्वरकों और कृषि उपकरणों का स्थानीय उत्पादन बढ़ाने की पहल जारी है। इसके अलावा डिजिटल स्वाधीनता के तहत स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकों के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, ऊर्जा स्वतंत्रता के तहत नवीनीकरणीय ऊर्जा, जैसे- सौर, पवन, और हाइड्रोजन ऊर्जा पर निवेश कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने की मुहिम जारी है। वहीं, सरकारी योजनाओं के तहत पीएम स्वनिधि योजना, जैसे- छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अभियान को 2020 में शुरू किया था और इसे 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य से जोड़ा गया है। इसके तहत रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, और कृषि जैसे सभी प्रमुख क्षेत्र आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और नीति स्तर पर काम करना होगा जो देश की समग्र ताकत और स्थिरता को बढ़ाएगा। जहां तक विदेशी निर्भरता कम करने के मुख्य उपाय की बात है तो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की कोशिशें तेज हैं। इसके तहत रक्षा उपकरणों, हथियारों और तकनीकी संसाधनों का अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादन करने की पहल तेज है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है, जिसमें 3,000 से अधिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन सुनिश्चित किया गया है। इससे विदेशों से रक्षा उपकरणों की निर्भरता कम होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है।

वहीं, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके दृष्टिगत 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत घरेलू उद्योगों और एमएसएमइज (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को समर्थन देने को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आयात की जगह घरेलू उत्पादन बढ़े। वहीं, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के बीच सहयोग बढ़ाकर तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने की मुहिम तेज की गई है। वहीं, औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण करते हुए रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना, निवेश और प्रोत्साहन से स्वदेशी उत्पादन को तेजी देने की पहल परवान चढ़ाई जा चुकी है। वहीं, निर्यात और व्यापार सुधार के तहत बंदरगाहों और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और सक्षम बनाने की मुहिम तेज है, ताकि विदेशी निर्भरता कम होकर स्वदेशी व्यापार बढ़े। वहीं, विदेशी निर्भरता घटाने के लिए ऊर्जा, कृषि, और डिजिटल क्षेत्र में स्थानीय समाधानों को अपनाने और विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए उन सरकारी नीतियों और योजनाओं को लागू किया जा रहा है जो विदेशी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि चिप्स (सेमीकंडक्टर चिप्स) व जहाज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में ही विकसित करने होंगे ताकि विदेशी निर्भरता समाप्त हो। आत्मनिर्भरता ही देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत नींव है। इस प्रकार, स्वदेशीकरण, स्थानीय उत्पादन, अनुसंधान विकास, और नीति स्तर पर सुधार करके भारत अपनी विदेशी निर्भरता कम कर सकता है। यही वजह है कि भारत में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के कई प्रभावी उपाय हैं जो सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर अपनाए जा सकते हैं। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और बढ़ावा देने के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करना है ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करें। इससे घरेलू उद्योगों को समर्थन मिलेगा। वहीं, सरकार के समर्थन और प्रोत्साहन से सरकार को स्वदेशी उत्पादकों को अनुदान, सहूलियत भरे ऋण, टैक्स छूट जैसे वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें। साथ ही सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार अभियान चलाकर स्वदेशी वस्तुओं की महत्ता और गुणवत्ता जनता तक पहुंचाई जाए। गुणवत्ता में सुधार और नए डिजाइन से स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग बेहतर करनी होगी ताकि वे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बने रहें। इस हेतु उत्पादों के नए डिजाइनों और तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। वहीं, स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों और सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों के प्रचार के लिए स्थानीय स्तर पर मेले, हाट और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा।

विकास की एक नई परिभाषा गढ़ता भारत

आज का भारत विकास की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। पहले जब हम अंत्योदय की बात करते थे तो इसका अर्थ था कि हर गरीब को अन्न, वस्त्र और आश्रय मिल जाए। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज अंत्योदय केवल पेट भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, डिजिटल सुविधा, कौशल विकास और आत्मसम्मान जैसे कई आयाम शामिल हो गए हैं। यही वजह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वह विचार आज और भी सजीव लगता है, जिसमें उन्होंने कहा था–ह्लगरीबी केवल भौतिक अभाव का नाम नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास में बाधा है।ह्व

गरीबी अब केवल आय की कमी का नाम नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और गरिमा से वंचित होना भी गरीबी का ही रूप है। यही कारण है कि आज इसे बहुआयामी गरीबी कहा जाता है, जो व्यक्ति की जीवन-गुणवत्ता के कई पहलुओं को मापता है। भारत में 2013-14 में लगभग 29% लोग बहुआयामी गरीबी में थे, पर 2022-23 में यह घटकर केवल 11% रह गया, यानी करीब 25 करोड़ लोग इससे बाहर आए। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों ने गरीबी की इस परिभाषा से मुक्ति पाई। यही अंत्योदय का वास्तविक स्वरूप है–जब विकास केवल अन्न या आवास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर आयाम को गरिमा और अवसर से जोड़ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था–भारत की प्रगति मानवता के एक-छठे हिस्से की नियति है।ह्व यह कथन केवल आदर्श नहीं, बल्कि तथ्य है। जब इतने करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। मोदी सरकार की कई योजनाएँ इसी दर्शन को आगे बढ़ाती हैं। उज्ज्वला योजना ने गरीब माताओं के जीवन से धुआँ हटाया, आयुष्मान भारत ने पाँच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा दी, प्रधानमंत्री आवास योजना ने पक्के घर दिए और स्वच्छ भारत मिशन ने शौचालयों के माध्यम से स्वास्थ्य व सम्मान दोनों पहुँचाया। यह सब मिलकर दिखाता है कि अंत्योदय अब केवल बुनियादी जरूरतों की पूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरिमा और आत्मसम्मान से भरे जीवन का नया आधार है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था–ह्लगरीबों को गरीबी से बाहर निकालना ही सच्चा राष्ट्रधर्म है।ह्व उनकी यह बात आज और भी गूंजती है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गरीबी से मुक्ति का अभियान अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में शून्य गरीबी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लाखों परिवार चिन्हित किए गए हैं और उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि 2027 तक राज्य को गरीबी-मुक्त घोषित किया जा सके। जब किसी परिवार को एक ही दरवाजे से उज्ज्वला, आयुष्मान, जल जीवन मिशन और आवास योजना का लाभ मिलता है, तब अंत्योदय का वास्तविक अर्थ सामने आता है।

आज का अंत्योदय केवल मदद भर नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है। मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसे प्रयासों ने युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया है। सड़क, बिजली और इंटरनेट गाँवों तक पहुँचाकर अब अवसरों की खाई घट रही है। इसका सीधा अर्थ है कि अंत्योदय अब ह्लसहायताह्व से आगे बढ़कर ह्लसशक्तिकरणह्व का नाम बन गया है।

लेकिन केवल सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। अंत्योदय तभी संपूर्ण होगा जब समाज की चेतना भी साथ आए। जब कोई स्वयंसेवक किसी बच्चे को अक्षरज्ञान देता है, कोई डॉक्टर दूरदराज में निःशुल्क सेवा करता है, या युवा मिलकर किसी गाँव को स्वच्छ बनाते हैं, तो यह भी अंत्योदय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह कथन यहाँ विशेष मार्गदर्शक है– विकास की धारा तभी पूर्ण होगी जब उसका स्पर्श समाज के अंतिम तट तक पहुँचे।

आज भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया है। यानी लगभग 94 करोड़ लोग अब किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि अंत्योदय अब करोड़ों परिवारों के जीवन में आत्मविश्वास और आशा का दीपक बन गया है। बहुआयामी गरीबी (टढक) की गिरावट और सामाजिक सुरक्षा में यह बढ़ोतरी, दोनों मिलकर यह सिद्ध करते हैं कि अंत्योदय अब केवल नीति की अवधारणा नहीं, बल्कि धरातल पर बदलती हकीकत है। निष्कर्ष यही है कि अंत्योदय की बदलती परिभाषा अब रोटी-कपड़ा-मकान तक सीमित नहीं है। आज यह स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल अवसर, गरिमा और आत्मनिर्भरता का नया नाम है। जब कोई माँ धुएँ से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जीती है, कोई बच्चा डिजिटल शिक्षा से जुड़ता है, कोई किसान सम्मानजनक आय पाता है और कोई गरीब परिवार पक्के घर में सपनों को सँजोता है, तभी राष्ट्र की प्रगति सार्थक होती है। और अंत में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन शब्दों से बेहतर इस बदलाव की आत्मा को कोई और व्यक्त नहीं कर सकता–ह्लकोई भी समाज तभी महान कहलाता है जब उसकी सबसे कमजोर कड़ी भी सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सके।ह्व यही अंत्योदय की बदलती परिभाषा है, और यही भारत की बदलती तस्वीर।

घूँघट की बगावत

28 सितम्बर 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

काशी की गंगा जमुनी तहजीब का नजारा

भारत की सांस्कृतिक एकता हर तनाव पर भारी: एक तरफ नमाज तो दूसरी ओर लीला

वाराणसी। गत दिनों बृहस्पतिवार की शाम को लाटभैरव मंदिर के लीलास्थल पर काशी की गंगा जमुनी तहजीब का नजारा देखने को मिला। एक तरफ मगरिब की नमाज की अजान में अल्लाह हू अकबर की गूंज थी, तो दूसरी तरफ ढोलक की थाप और मंजीरे की खनक के बीच तुलसीदास के मंगल भवन अमंगल हारी... की स्वरलहरियां गूंज रही थीं। शाम 4:45 बजे लाटभैरव मंदिर के विशाल प्रांगण में श्री आदि लाटभैरव वरुणा-संगम काशी की रामलीला शुरू हुई। चबूतरे के पूर्वी हिस्से में रामचरितमानस का दोहा सीता चरन चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारन कागा... गूंज रहा था। ठीक पांच बजे, चबूतरे के पश्चिमी हिस्से में नमाजियों ने अल्लाह को याद किया।

रामलीला के व्यास दयाशंकर त्रिपाठी जयंत के संवादों को दिशा दे रहे थे, तो दूसरी ओर इमाम नमाज का क्रम आगे बढ़ा रहे थे। दोनों आयोजन एक साथ, एक ही स्थान पर, बिना किसी व्यवधान के चलते रहे।

नमाज से पहले शुरू हुई रामलीला नमाज के बाद भी निर्बाध चलती रही। खास बात यह रही कि नमाज के बाद कई मुस्लिम भाइयों ने भी रामलीला के दर्शक के रूप में न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि रामलीला में प्रसाद स्वरूप तुलसी और मिश्री भी ग्रहण किया। यह दृश्य न सिर्फ आंखों को सुकून दे रहा था, बल्कि दिल को यह यकीन भी दिला रहा था कि भारत की सांस्कृतिक एकता हर तनाव पर भारी है। काशी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, बल्कि प्रेम, एकता और सहिष्णुता का भी गढ़ है।

लाटभैरव की यह रामलीला कोई साधारण आयोजन नहीं है। यह 500 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जिसकी शुरूआत गोस्वामी तुलसीदास और उनके परम मित्र मेघा भगत ने की थी। लाटभैरव मंदिर-मस्जिद के बीच की इस फर्श पर जयंत नेत्रभंग की लीला मस्जिद के निर्माण से भी पहले से होती आ रही है। लाटभैरव रामलीला के प्रधानमंत्री एडवोकेट कन्हैयालाल यादव ने इसे भारत की विविधता में एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा यहां नमाज और रामलीला का एक साथ होना हमारी सांस्कृतिक धरोहर की ताकत दिखाता है। लाटभैरव की रामलीला की परंपरा तुलसीदास के दौर से चली आ रही है और वर्तमान में अब काशी की गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत उदाहरण है।

आपसी सौहार्द और भाईचारे की एक मिसाल

स्वेच्छा से सामूहिक निर्णय और भू-दान

लाटघाट। क्षेत्र के रामनगर गांव में आपसी सौहार्द और भाईचारे की एक मिसाल पेश करते हुए एक हिंदू परिवार ने मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दान में दे दी। यह जमीन रसूलपुर भदौरा गांव में स्थित है और रामनगर से ओढ़रा-सलेमपुर संपर्क मार्ग पर आती है। पांचों भाइयों के इस कार्य की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। रामनगर गांव निवासी राकेश कुमार सिंह, दिनेश सिंह, सुधाकर सिंह, ओंकार सिंह और अखिलेश सिंह ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया और स्वेच्छा से जमीन दान कर दी। राकेश सिंह ने बताया कि हमने पूरी सहमति और खुशी से यह जमीन हाजीपुर गांव के मुसलमान भाइयों को कब्रिस्तान के लिए दान दी है। यह हमारी तरफ से एक छोटा प्रयास है भाईचारे को मजबूत करने का। भदौरा रसूलपुर के प्रधान प्रतिनिधि सईदुल आजमी ने इसे सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि यह बहुत कीमती जमीन है, जिसे भाईचारे की भावना से दान किया गया है। ऐसे कदम समाज को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं।

हाजीपुर गांव के निवासी मुनव्वर ने बताया कि हमारे गांव में पिछले 25 वर्षों से मुस्लिम कब्रिस्तान नहीं है। हमें शवों को दफनाने के लिए रसूलपुर भदौरा गांव जाना पड़ता था और वहां भी पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। अब रामनगर गांव के इस परिवार ने हमारी मुश्किल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। हम सब बहुत खुश हैं और उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बताते चलें कि हाजीपुर गांव में लगभग 8-10 मुस्लिम परिवार निवास करते हैं, जिन्हें लंबे समय से कब्रिस्तान की जमीन की जरूरत थी। अब जब यह जमीन उन्हें मिली है, पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा हो रही है, हर कोई पांचों भाइयों के इस कार्य की सराहना कर रहा है।

रूट सिस्टम के विरोध में ई-रिक्शा चालकों का प्रदर्शन

- जुलूस की शक्ल में निकले ई-रिक्शा चालकों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया
- नए रूट सिस्टम से उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा

बस्ती। रूट सिस्टम के विरोध में सीटू के नेतृत्व में ई-रिक्शा चालकों ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। चालक गांधीनगर इलाके में नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में निकले और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। ई-रिक्शा चालकों का कहना है कि नए रूट सिस्टम से उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा। उनका आरोप है कि तय रूट के बाहर मिलने वाली सवारी से उन्हें रोजाना की आमदनी पूरी होती है, लेकिन प्रशासन की पाबंदी से उनकी आय घट जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से बढ़े हुए खर्च की वजह से वैसे ही हालात खराब हैं, ऊपर से यह नया नियम उन्हें कर्ज में डूबो देगा। वहीं, टैक्सी यूनियन के एक गुट के अध्यक्ष हारुन ने इस आंदोलन से दूरी बना ली। उन्होंने साफ कहा कि वे रूट सिस्टम के पक्ष में हैं और किसी भी तरह के विरोध का हिस्सा नहीं होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रूट सिस्टम लागू करने का मकसद शहर में जाम की समस्या को कम करना और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना है।

बाल शिक्षा के लिए महिलाओं की अनोखी पहल

पुरानी बस्ती में एक नई लाइब्रेरी स्थापित

बस्ती। इनरव्हील क्लब बस्ती मिडटाउन से जुड़ी महिलाओं ने बच्चों की शिक्षा के लिए अनोखी पहल करते हुए लाइब्रेरी खोली है। इससे गरीब तबके के बच्चे पढ़-लिख कर आगे बढ़ सकेंगे। क्लब सदस्यों ने कहा कि इससे बच्चों को काफी सहूलियत मिलेगी। क्लब ने सामाजिक सेवाओं की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। क्लब ने पुरानी बस्ती में एक नई लाइब्रेरी स्थापित कराई है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरणादायक और शांत वातावरण मिल सकेगा। इसके साथ ही, स्कूल में इनवर्टर की भी व्यवस्था की गई, जिससे बिजली की समस्या के चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। क्लब की अध्यक्ष आशा अग्रवाल और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर इसका शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों को शिक्षाप्रद और रोचक कहानियों वाली पुस्तकें भेंट की गईं। क्लब की अध्यक्ष ने कहा, हमारा उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराना है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, बढ़े और अपने सपनों को साकार करे।

नेशन बिल्डर्स अवार्ड सम्मानित हुए दो शिक्षक

गोरखपुर। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के दो शिक्षकों को नागपाल चौरिटेबल ट्रस्ट, श्रीगंगानगर, राजस्थान की ओर से नेशन बिल्डर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इन शिक्षकों में कंप्यूटर विज्ञान विभाग के डॉ. पवन कुमार पाण्डेय और बीएड विभाग के डॉ. सुभाष चंद्रा शामिल हैं। यह सम्मान देश और विदेश के 70 और शिक्षकों को मिला है। प्राचार्य प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल हमारे शिक्षकों की व्यक्तिगत प्रतिभा और समर्पण का परिणाम है, बल्कि हमारे महाविद्यालय की शैक्षणिक परंपरा और गुणवत्ता का भी प्रतीक है।

सेवा पखवाड़ा अंतर्गत विद्यार्थियों ने किया कारागार भ्रमण, ली कारागारीय गतिविधियों की जानकारी

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत आज छात्रों के लिए एक विशेष भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने जेल अधीक्षक डी. के. पांडेय और जेलर अरुण कुमार कुशवाहा के मार्गदर्शन में गोरखपुर जिला कारागार का दौरा किया। कार्यक्रम राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल की प्रेरणा तथा कुलपति प्रो. पूनम टंडन के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। प्रो. दिव्या रानी सिंह ने कार्यक्रम का संयोजन किया और संचालन किया। भ्रमण के दौरान छात्रों को कारागार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। इनमें शैक्षिक कक्षाएँ शामिल हैं, जो बंदियों को साक्षर बनाने और उच्च शिक्षा से जोड़ने हेतु आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत सिलाई-कढ़ाई, बढ़ईगिरी, बुनाई, पेंटिंग और कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, ताकि रिहाई के बाद कैदी आत्मनिर्भर बन सकें। स्वच्छता और स्वास्थ्य पहल के तहत कारागार परिसर में योग, ध्यान और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में कविता-पाठ, भजन-कीर्तन, रंगमंच और उत्सव आधारित कार्यक्रम शामिल हैं। कैदियों द्वारा तैयार कपड़े, हस्तशिल्प और खाद्य सामग्री स्थानीय बाजार और सरकारी संस्थानों आपूर्ति की जाती है। छात्रों ने महिला बैरक का निरीक्षण भी किया और महिला कैदियों तथा उनके बच्चों से संवाद किया। छह वर्ष तक के बच्चे अपनी माताओं के साथ कारागार में रह सकते हैं और उन्हें शिक्षा हेतु विशेष केंद्र भेजा जाता है। कारागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे कैदी दूरस्थ अदालत सुनवाई में भाग ले सकते हैं। लाइब्रेरी और स्वास्थ्य क्लिनिक भी चलाए जाते हैं, जहाँ डॉक्टर नियमित रूप से विज़िट करते हैं। छात्रों ने कैदियों से संवाद कर उनके अनुभव सुने। कई कैदियों ने बताया कि शिक्षा और प्रशिक्षण उनके जीवन को सुधारने और समाज में सम्मानजनक पहचान पाने का माध्यम बन रहे हैं। विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक गार्गी पांडेय और एम.एससी. फूड टेक्नोलॉजी के छात्र-छात्राएँ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

शासकीय विद्यालयों के 51 शिक्षकों को मिला 'नेशन बिल्डर्स अवार्ड'

इंदौर। रोटरी क्लब ऑफ इंदौर प्रोफेशनल्स द्वारा जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों के 51 शिक्षकों को 'नेशन बिल्डर अवार्ड' से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रेनांसा यूनिवर्सिटी के निदेशक एवं शिक्षाविद स्वप्निल कोठारी ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की सबसे अहम कड़ी है और यह सबसे सम्मानजनक पेशा है। विशेष अतिथि संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग, इंदौर अनीता चौहान ने कहा कि अभाव में भी व कम संसाधनों में भी सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने प्रयासों के द्वारा विद्यार्थियों में उत्कृष्टता लाते हैं। रोटरी मंडलाध्यक्ष सुशील मल्होत्रा ने आधुनिक शिक्षा में संस्कारों के समावेश के महत्व पर प्रकाश डाला व बताया की किस तरह रोटरी पूर्ण विश्व मे समाज सेवा के नए मापदंड स्थापित कर रहा है। पूर्व रोटरी जोन चेयरमेन नितिन डफरिया ने बताया कि किस तरह रोटरी अपनी गतिविधियों के द्वारा राष्ट्र में पूर्ण शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर शिक्षाविद उपेंद्र धर ने रोटरी क्लब की प्रशंसा की व कहा कि किस तरह एक बार पढ़ने पर जीवन भर विद्यार्थी शिक्षकों का सम्मान करते हैं।

क्लब के अध्यक्ष भानु तापडिया ने सभी शिक्षकों और अतिथियों का स्वागत किया तथा सभी शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण में इस महान योगदान के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। क्लब के सचिव सुनील अत्री ने सबका आभार माना। क्लब की लिटरेसी डायरेक्टर दिव्या डफरिया ने आज के इस आयोजन का महत्व सबके सामने रखा।

अतिथियों ने शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में रोटरी मंडल की प्रथम महिला रूबी मल्होत्रा, रोटरी पब्लिक इमेज चेयर घनश्याम सिंह, साक्षरता को-चेयर रेणु सिंह सहित अनेक रोटेरियन्स शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश खण्डेलवाल व पूजा अग्रवाल ने किया। शिक्षकों की तरफ से आभार भगवती प्रसाद पंडित एवं रोटरी क्लब की तरफ से अक्षत गुप्ता ने व्यक्त किया।

अनुराग कश्यप की धारदार सिनेमा वापसी

अनुराग कश्यप फिर से उसी दौर में लौट आए हैं। छोटे शहरों के गुंडों, स्थानीय नेताओं और पहलवानों, और भ्रष्ट पुलिसवालों के बीच के गठजोड़ की कहानी, जहाँ लोग निशाना साधते हैं और किसी को, न सिर्फ. आँखों के बीच, बल्कि कुछ ऐसे निचले तबकों के बीच भी, जिनका पूरबिया में रंगीन वर्णन है।

ऐश्वर्या ठाकरे की पहली फिल्म ₹निशानची₹ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। निर्देशक-लेखक अनुराग कश्यप को जानने वाले जानते हैं कि फिल्म निमार्ता प्रतिभा से पहले विरासत के बच्चों को महत्व देने में कभी विश्वास नहीं करते। लेकिन जिस दिन शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के पोते के साथ इस फिल्म की घोषणा हुई, इसका सीधा मतलब था कि अनुराग ने ऐश्वर्या में कुछ ऐसा देखा जो दूसरों को अभी तक नहीं पता था। इसके अलावा, ऐश्वर्या, जिन्होंने राजनीति की बजाय फिल्मों को चुना और ₹बाजीराव मस्तानी₹ में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, ने फिल्मों में आने के लिए अपना समय लिया है। चाहे उनकी भाषा शैली हो, स्क्रीन पर उपस्थिति हो या अभिनय क्षमता, ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़े पर्दे पर आने से पहले फिल्मों की कई अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझा है। लेकिन क्या वह मनोज बाजपेयी, अभय देओल, तापसी पन्नू और विक्की कौशल की तरह अनुराग कश्यप की फिल्म का निर्देशन कर पा रहे हैं, या इस बार फिल्म निमार्ता ही उनकी नाव डुबो रहे हैं? आइए जानते हैं।

कहानी

निशानची की शुरूआत डबलू, बबलू (ऐश्वर्य ठाकरे) और रिंकू से होती है, जो एक बैंक लूटने में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। नर्तकी रिंकी और उसका मासूम देवर डबलू किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि उन सबका सरगना और सबसे बहादुर बबलू उर्फ टोनी मंटेना पकड़ा जाता है और उसे 7 साल की जेल हो जाती है।

2000 के शुरूआती वर्षों में उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटित, निशानची दो समय-सीमाओं में चलती है। पहली में, बबलू अपने चाचा की साज़िश को समझ नहीं पाता और 7 से 10 साल की सजा काटता है, जबकि पिछली समय-सीमा उसके माता-पिता की प्रेम कहानी और संघर्ष की कहानी के द्वार खोलती है। पहले भाग में, पता चलता है कि मंजरी (मोनिका पंवार) और जबरदस्त (विनीत कुमार सिंह), जो एथलीट थे, एक-दूसरे से प्यार करते थे और शादी के बाद उन्हें जुड़वाँ बच्चे हुए। हालांकि, काम पर मिले अनुचित व्यवहार से उपजी थकान और संघर्ष के चलते, जबरदस्त एक ऐसी कंपनी में नौकरी कर लेता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था और एक ऐसा अपराध कर बैठता है जो उसकी पत्नी और बच्चों की किस्मत बदल देता है।

दूसरी ओर, वर्तमान घटनाक्रम रिंकी की कहानी पर आधारित है कि कैसे वह बबलू से मिलती है, उस-के चाचा अंबिका प्रसाद (कुमुद मिश्रा) की घर के प्रति लालसा से जूझती है और जेल में बंद बबलू के प्यार के साथ रहती है। लेकिन जब कोई सोचता है कि मंजरी, डबलू और रिंकी इन सब से बचने के लिए किसी संकरी गली में चले गए होंगे, तो कहानी एक बड़ा मोड़ ले लेती है, जो पहले भाग को खत्म करने और निशानची भाग 2 की शुरूआत करने के लिए एकदम सही जगह बन जाती है।

'निशानची' की शुरूआत अनुराग कश्यप द्वारा कानपुर में 2006 में शुरू की गई एक दमदार शुरूआत से होती है, जहाँ शहर में अजान की तेज आवाज गूंजती है और कुछ ही सेकंड बाद मंदिर की घंटियाँ भी बजने लगती हैं। ऐसा सिर्फ.कश्यप की फि ल्म में ही हो सकता है, और हम इसे इसी जादू के लिए देखते हैं। जल्द ही हमें जुड़वाँ भाइयों, बबलू (उर्फ टोनी मंटेना) और डबलू से मिलवाया जाता है, जिनका किरदार नवोदित ऐश्वर्या ठाकरे ने खूबसूरती से निभाया है। अपनी साथी रिंकू (वेदिका पिंटो) के साथ, वे एक बैंक लूटने का फैसला करते हैं, लेकिन भागते समय बबलू पकड़ा जाता है। फिर यह रोमांचक सफर शुरू होता है, जो हमें उस समय में ले जाता है जब वे पैदा भी नहीं हुए थे, और फिर कैसे यह परिवार अंबिका प्रसाद (कुमुद मिश्रा) के संपर्क में आया, जिसने कई बार उनकी किस्मत बदली। फिल्म का मुख्य आकर्षण विनीत कुमार सिंह और मोनिका पंवार का फ्लैशबैक सीक्वेंस है। खेल के प्रति अपने जुनून से एक साथ आए इस जोड़े की केमिस्ट्री और प्रेम कहानी देखने लायक है। इसके अलावा, कलाकारों ने इतना दमदार अभिनय किया है कि एक समय तो आपको ऐसा लगता है जैसे यह उनकी ही फिल्म है। संघर्षरत पहलवान, जबरदस्त के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति की हताशा को दशार्ते हैं जो अपनी योग्यता साबित करना चाहता है, लेकिन राजनीति के बोझ तले दबा हुआ है। दूसरी ओर, मोनिका मंजरी का किरदार निभाती हैं, जो एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला है जो समानता के साथ एक परिवार बनाने में कामयाब होती है, और पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना जानती है।

कईवर्षों तक आर्थिक तंगी झेली डब्बू मलिक ने

बॉलीवुड के फेमस सिंगर अनु मलिक के भाई डब्बू मलिक ने कई वर्षों तक भयंकर आर्थिक तंगी झेली है। अब उन्होंने इस बारे में खुलकर बातें की। उन्होंने बताया कि अपने बच्चों, अमल और अरमान मलिक को अच्छी एजुकेशन देने के लिए उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी थी। डब्बू मलिक ने बीते दिनों की कहानी बताते हुए कहा कि उनके अपने पिता सरदार मलिक ने उनका करियर खत्म हो जाने के बाद उन्हें और उनके भाइयों को संगीत की शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने डब्बू पर जोर दिया था कि वह अमल और अरमान को संगीत की अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करें। हालांकि डब्बू की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी और उन्हें उन सिंगर्स से अजीबोगरीब काम मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनके साथ उन्होंने पहले खुद कम्पोजर के रूप में काम किया था।

जान्हवी कपूर ने मां को कुछ इस अंदाज में याद किया

'होमबाउंड' के मुंबई प्रीमियर की शाम न सिर्फ फिल्मी दुनिया के लिए ऐतिहासिक रही, बल्कि यादगार लम्हा भी बन गई। जब इस मौके पर जान्हवी कपूर ने अपनी दिवंगत मां और हिंदी सिनेमा की महान अदाकारा श्रीदेवी को ट्रिब्यूट देने का एक अनोखा और बेहद दिल छू लेने वाला तरीका चुना।

उन्होंने वह खास रॉयल ब्लू और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी, जिसे श्रीदेवी ने साल 2017 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन में पहना था। उस वक्त यह साड़ी सबका ध्यान खींच चुकी थीं और अब जब जहान्वी ने इसे पहना, तो यह पल और भी खास और इमोशनल हो गया।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com